सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 191 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 25 अप्रैल 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

वेदांता प्लांट हादसे में 25 मौतें, 3 की हालत अब भी गंभीर

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए ब्लास्ट में अब तक 25 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हादसे में 36 लोग झुलसे थे, जिनमें से 3 मरीजों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जबकि 5 मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वहीं 2 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। घटना के 10 दिन बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि घटना की जवाबदेही तय करे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (ष्ठत्रक्क) को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर डिटेल से रिपोर्ट मांगी है।

के कविता ने बनाई अपनी राजनीतिक पार्टी

हैदराबाद। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की पूर्व नेता के कविता ने आज अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। के कविता की पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र सेना है। महीनों पहले के कविता को उनके ही पिता की पार्टी बीआरएस से निलंबित कर दिया गया था। के कविता को बीते साल बीआरएस से निलंबित किया गया था। के कविता की नई पार्टी की लॉन्चिंग हैदराबाद में हुई। खास बात ये है कि बीआरएस का पुराना नाम भी टीआरएस (तेलंगाना राष्ट्र समिति) था, जिसे बाद में बदलकर (भारत राष्ट्र समिति) कर दिया गया था।

छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने वालों की होगी जांच

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता के बाद अब राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में सरेंडर करने वाले लोग सही हैं और उन्हें ही पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिले। राज्य सरकार के इस फैसले के तहत अब नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षक को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की पूरी जानकारी जुटाकर उसका रिकॉर्ड तैयार करेंगे और उसे अपडेट भी करेंगे।

ई-केवाईसी करने अवैध वसूली की, 9 सीएससी ब्लैकलिस्ट हुए

जशपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी प्रक्रिया के नाम पर अवैध वसूली के मामलों पर जशपुर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर रोहित व्यास ने 9 कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के खिलाफ निलंबन और पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि कुछ चॉइस सेंटर संचालक ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से ई-केवाईसी अपडेट के नाम पर अनधिकृत रूप से पैसे वसूल रहे थे। प्रशासन ने जिन ग्राम पंचायतों में कार्रवाई की है, उनमें बघिमा, लोदाम, काडरो, पंडरीपानी, कुड़खेलखजरी, कोहपानी, लरंगा, सेमरकछार और गोरिया शामिल हैं। इन केंद्रों की आईडी ब्लॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

भिलाई में एसटीएफ जवान की पत्नी व बेटे की हत्या, महिला ने चाकू से किया हमला

स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के एसटीएफ कॉलोनी की घटना, एक बेटी ने छिपकर बचाई जान

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बटालियन के एसटीएफ कॉलोनी में शनिवार को खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एसटीएफ के जवान की पत्नी व उसके 9 साल के बेटे की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इस पूरी वारदात को एक महिला ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है महिला सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच घर में घुसी और एसटीएफजवान पत्नी और उसके 9 साल के बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। एक बेटी को भी चाकू लगा है, जिसने बाथरूम में छिपकर अपनी जान बचाई। यह पूरा मामला स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर एसटीएफमें पदस्थ आरक्षक ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव अपने तीन बच्चो आदित्य यादव व दो बेटियों के साथ एसटीएफकॉलोनी बी ब्लॉक के डी-15 में रहती है। आरक्षक ललितेश यादव 15 दिन की छुट्टियां लेकर घर आया हुआ था। शनिवार की सुबह पति ललितेश यादव टिकट रिजर्वेशन कराने गया था इस बीच 25 वर्षीय सरोजनी भारद्धाज घर में घुसी आर धारदार चाकू से रीना यादव और बच्चों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। हमले में बेटे आदित्य यादव की मौके पर ही मौत हो गई।

घायल अवस्था में मां ने बच्चों को बचाने घर से भगाया

जब सरोजनी हमला कर रही थी उस दौरान रीना यादव ने अपनी बेटियों को भागने के लिए कहा। एक बेटी किसी तरह बाहर निकलकर पड़ोसियों को सूचना देने में सफल रही, जबकि दूसरी बाथरूम में छिप गई। सूचना मिलने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और महिला को पकड़ लिया। लोगों ने उसके हाथ से चाकू छीनकर उसे बांधा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपिया को हिरासत में लिया और रीना यादव व बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। रीना यादव की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं दोनों बेटियों का इलाज चल रहा है।

एक दिन पहले भी घर पहुंची थी आरोपिया

सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि शुरुआती जांच व पूछताछ में पता चला है कि आरोपिया सरोजनी भारद्धाज एक दिन पहले यानी शुक्रवार को घर पहुंची थी। उस समय आरक्षक ललितेश यादव ने उसे समझाकर वापस भेज दिया था। बताया जा रहा है कि सरोजनी जांजगीर की रहने वाली है और दुर्ग में किराए के मकान में रह रही थी। सीएसपी तिवारी ने यह भी बताया कि आरोपिया एसटीएफ जवान की परिचित है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए विदेशी फंडिंग, बस्तर-धमतरी में 6.5 करोड़ रुपए खर्च

ईडी की जांच में खुलासा, प्रेस रिलीज जारी कर साझा की जानकारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सामने आया है कि अमेरिका से आए पैसों का इस्तेमाल बस्तर और धमतरी में धार्मिक गतिविधियों के विस्तार में की गई। ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की इस संबंध में जानकारी मीडिया से साझा की है।

जांच एजेंसी क मुताबिक, नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत लाए गए। अमेरिकी एजेंसी की ओर से जारी करीब 6.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के इलाकों में खर्च किए गए हैं। यह पूरा मामला 'द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI)' नामक संगठन और उससे जुड़े लोगों से जुड़ा है।

विदेशी नागरिक की हिरासत के बाद खुलासा

इस मामले में मिकाह मार्क नाम के विदेशी नागरिक को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने ईडी के लुकआउट सर्कुलर के आधार पर हिरासत में लिया। उसके पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनके जरिए भारत में कैश निकाला जा रहा था। ईडी ने 18 और 19 अप्रैल को देशभर में 6 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच में सामने आया कि अमेरिका के टूरिस्ट बैंक से जुड़े विदेशी डेबिट कार्ड भारत लाकर अलग-अलग राज्यों के एटीएम से बार-बार नकदी निकाली जा रही थी। ऐसा कर नियामकीय व्यवस्था और वित्तीय निगरानी तंत्र को चकमा दिया जा रहा था।

'टीटीआई' का नेटवर्क

यह पूरा मामला 'द टिमोथी इनिशिएटिव (टीटीआई)' नामक संगठन और उससे जुड़े लोगों से जुड़ा है। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि टीटीआई भारत में 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' के तहत पंजीकृत नहीं है, फिर भी यह संगठन भारत में सक्रिय था। टीटीआई खुद को एक वैश्विक मसीही संगठन के रूप में प्रस्तुत करता है, जो कथित तौर पर चर्च प्लांटिंग (नए चर्च की स्थापना) और लीडरशिप ट्रेनिंग के काम में लगा हुआ है।

भारत में लाए गए 95 करोड़ रुपए

जांच में यह भी सामने आया कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत में लाए गए। वहीं लेन-देन का रिकॉर्ड रखने के लिए ऑनलाइन बिलिंग और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे कथित तौर पर विदेश से ऑपरेट किया जा रहा था। छापेमारी में ईडी ने 25 विदेशी डेबिट कार्ड, 40 लाख रुपए नकद, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल सबूत और अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। एजेंसी का कहना है कि यह एक संगठित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क हो सकता है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल का संकट नहीं, सरकार बोली- सप्लाई सामान्य

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट से बचें।

विभाग के अनुसार पश्चिम एशिया में बने हालात को देखते हुए राज्य सरकार लगातार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संपर्क में है, ताकि प्रदेश में ईंधन आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। अधिकारियों ने बताया कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और आपूर्ति की नियमित साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। राज्य में संचालित 2516 पेट्रोल पंपों और प्रमुख ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। मार्च में पेट्रोल की जरूरत के मुकाबले 126 प्रतिशत और डीजल की 183 प्रतिशत आपूर्ति दर्ज की गई, जबकि अप्रैल में भी मांग के अनुरूप सप्लाई जारी है।

खाद्य विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में लगभग 22 दिनों की जरूरत के बराबर पेट्रोल और 15 दिनों की खपत के लिए डीजल उपलब्ध है। विभाग ने कहा कि किसी भी तरह के संकट की स्थिति नहीं है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक के लिए जिलों में आकस्मिक निरीक्षण और छापेमारी भी जारी है। राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं, वहीं शिकायतों के लिए विभागीय कॉल सेंटर भी संचालित किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई, छह पुलिस अधिकारी निलंबित

चुनाव के दौरान अनियमितता और पक्षपात करने के आरोप

कोलकाता। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान गंभीर अनियमितता और पक्षपात करने के आरोप में छह पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। निलंबित हुए अधिकारियों में आईपीएस समेत एसडीपीओ और प्रभारी निरीक्षक भी शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने संदीप सरकार प्रभारी अधिकारी, हिंगलगंज पुलिस स्टेशन को निलंबित करने के साथ ही तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा संदीप गराई (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डायमंड हार्बर), साजल मंडल (एसडीपीओ, डायमंड हार्बर), मौसम चक्रवर्ती (इंस्पेक्टर इंचार्ज, डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन), अजय बाग (इंस्पेक्टर इंचार्ज, फ्लता पुलिस स्टेशन) और शुभेच्छा बाग (ऑफिसर इंचार्ज, उस्थी पुलिस स्टेशन) को निलंबित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही संदीप गराई को लेकर गृह मंत्रालय में उनके कैडर नियंत्रण प्राधिकारी को एक रिपोर्ट भेजने का भी आदेश जारी किया है।इसके अतिरिक्त, चुनाव जैसे संवेदनशील मामलों में अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए डायमंड हार्बर की पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशानी पाल को चेतावनी दी है।

सेंट्रल जेल में महिला बंदी के आत्महत्या प्रयास से हड़कंप

रायपुर। राजधानी की सेंट्रल जेल में महिला बंदी द्वारा आत्महत्या की कोशिश की खबर सामने आने के बाद जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। महिला कैदी आशिमा राव के हाथ की नस काटने की घटना ने जेल सुरक्षा और अंदरूनी व्यवस्थाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, महिला प्रकोष्ठ में बंद कैदी ने कथित तौर पर मानसिक तनाव के बीच आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद जेल प्रशासन ने उसे तत्काल उपचार उपलब्ध कराया, जहां प्राथमिक इलाज के दौरान उसके हाथ में टांके लगाए गए। घटना कुछ दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन मामला सामने आने के बाद परिजनों में नाराजगी बढ़ गई है। परिवार ने प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं।

नक्सलवाद कमजोर होते ही रेत माफियाओं का खेल शुरू, नदी पर अवैध सड़क बनाकर कर रहे तस्करी

श्रीकंचनपथ न्यूज

बीजापुर। जिले में नक्सलवाद के कमजोर पड़ते ही अब रेत तस्करों का नेटवर्क तेजी से पैर पसारने लगा है। भोपालपटनम ब्लॉक के अटटूकपल्ली पंचायत अंतर्गत कोंडामौसम गांव में इंद्रावती नदी के भीतर ही करीब 200 मीटर लंबी सड़क बनाकर अवैध रेत तस्करी का रास्ता तैयार कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा निर्माण बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक नदी के बीच मुरूम और रेत डालकर सड़क बनाई गई है, साथ ही पाइप पुलिया डालकर नदी का पानी दूसरी ओर मोड़ दिया गया है, जिससे तस्करों को रेत निकालने और वाहनों की आवाजाही में आसानी हो सके। इस पूरे मामले में तेलंगाना के ठेकेदारों की सक्रिय भूमिका सामने आ रही है।

गांव के लोगों का आरोप है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है। बिना ग्रामसभा की अनुमति और बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए सड़क निर्माण कर दिया गया। ग्रामीण मोडेम गणपत पंच ने बताया कि सिर्फ नारियल फोड़कर काम शुरू कर दिया गया, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। विरोध करने पर भी अनसुना किया गया। वहीं ग्रामीण तलाड़ी इरैया ने कहा कि गांव में इस विषय पर कोई बैठक नहीं हुई, किसकी अनुमति से सड़क बनी यह हमें नहीं पता।

इंद्रावती नदी में पानी का प्रवाह रोककर पाइप के जरिए दिशा बदलना गंभीर पर्यावरणीय खतरा माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप और जलस्तर पर असर पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार यालम शिवेया, दूबा तुलसीराम और दूबा नागेय की जमीन से होकर सड़क बनाई गई है।

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, 44.5 डिग्री पाराः 2 डिग्री और बढ़ेगा तापमान

रायपुर में हीटवेव का अलर्ट 2 दिन बाद बारिश के आसार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं 25 से 27 अप्रैल तक मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है।

सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जहां

न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर में शुक्रवार को हीटवेव की स्थिति बन सकती है। यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के बाद प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसके बावजूद लू का असर बना रह सकता है।

संपादकीय

आप को बड़ा झटका

सात सांसदों के पाला बदलने से पंजाब में पार्टी कमजोर

पंजाब में विधानसभा चुनाव से सिर्फ दस महीने पहले, राज्यसभा के सात सांसदों द्वारा आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ने से पार्टी का संकट गहराता नजर आ रहा है। बगावती तेवरों वाले तीन राज्यसभा सदस्यों राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी में विभाजन की घोषणा करते हुए कहा है कि उच्च सदन में आप के दो-तिहाई सांसद यानी दस में सात सदस्यों ने एक गुट के रूप में भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का निर्णय कर लिया है। हाल के महीनों में खासे मुखर रहने वाले राघव चड्ढा को राज्यसभा में आप के उपनेता पद से हटाये जाने के बाद उनके द्वारा शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद तो विभाजन के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। विडंबना यह है कि राज्यसभा में राघव चड्ढा के स्थान पर आप के उप नेता की जगह लेने वाले अशोक मित्तल ने भी उनका ही साथ दिया है। इसमें दो राय नहीं कि बीते साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिये यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। एक समय था कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी में नई पीढ़ी का ऊर्जावान प्रतीक चेहरा माना जाता रहा है। अब वे ही आप नेतृत्व पर पार्टी के मूलभूत आदर्शों से पीछे हटने का आरोप लगा रहे हैं। राघव व पार्टी के अन्य बागी सांसदों ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी जनसरोकारों को प्राथमिकता देने के बजाय निजी लाभ को तरजीह दे रही है। उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ही हैं। जिन्हें पंजाब में मान सरकार की बागडोर दिल्ली से संचालित करने वाला माना जाता रहा है। जैसा कि आपेक्षित था, आबकारी नीति मामले में मुश्किल में फंसे और अदालती लड़ाई लड़ रहे केजरीवाल ने इन सांसदों पर विश्वास तोड़ने और पंजाब की जनता से छल करने का आरोप लगाया है।

> “ हाल के महीनों में खासे मुखर रहने वाले राघव चड्ढा को राज्यसभा में आप के उपनेता पद से हटाये जाने के बाद उनके द्वारा शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद तो विभाजन के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। विडंबना यह है कि राज्यसभा में राघव चड्ढा के स्थान पर आप के उप नेता की जगह लेने वाले अशोक मित्तल ने भी उनका ही साथ दिया है। इसमें दो राय नहीं कि बीते साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिये यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। एक समय था कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी में नई पीढ़ी का ऊर्जावान प्रतीक चेहरा माना जाता रहा है।

केजरीवाल ने आप से अलग होने वाले सांसदों पर पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात करने वाला बताया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी केजरीवाल के निशाने पर है, जिस पर उन्होंने सुनियोजित साजिश करके आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वास्तव में भाजपा सीमावर्ती राज्य पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जड़ें मजबूत करने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में भगवा पार्टी ने हाल के वर्षों में पंजाब के कई कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में करने में कामयाबी पायी है। निश्चित रूप से राज्य सभा में आप के दो तिहाई सांसदों का टूटकर भाजपा में मिलना आम आदमी पार्टी के लिये बड़ी चुनौती है। जिसके चलते पंजाब में अपनी खोई जमीन पाने के लिये पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आप के कुछ और नेता आगामी दिनों में भाजपा का दामन थाम लें। लेकिन यहां सवाल आप सुप्रीमो पर उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने इन नेताओं को राज्यसभा का टिकट देते वक्त पार्टी की रीति-नीतियों की कसौटी पर परखा था या फिर पार्टी की आर्थिक प्राथमिकताओं को ही उनकी योग्यता मान लिया गया था। जाहिर है ये लोग सार्वजनिक जीवन में बहुत चर्चित चेहरे होने के बजाय आर्थिक रूप से समृद्ध लोग रहे हैं। जब चयन में आर्थिक प्राथमिकताएं होती हैं तो चयनित सदस्यों के निर्णय में भी लाभ-हानि का गणित ही प्रभावी रहता है। यहां सवाल कुछ सासंदों के कारोबारी छिद्रों पर सरकारी एजेंसियों का दबाव का भी है, जिन पर पिछले दिनों कार्रवाई भी हुई थी। अनुमान लगाये जा रहे हैं कि शायद इस कार्रवाई के बाद विभिन्न कारोबार से जुड़े अन्य सांसद भी दबाव में आ गए। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ राजग की धुलाई मशीन से गुजरना ज्यादा सुरक्षित महसूस किया। बहरहाल, इस घटनाक्रम ने अन्य राज्यों में विपक्षी दलों के लिये भी खतरे की घंटी बजा दी है। निश्चय ही इंडी गठबंधन के लिये अपने दलों को एकजुट रखना आने वाले दिनों चुनौती साबित हो सकता है।

मुक्त प्रवाह में खलल के बीच मछुआरे की सुध

लेफ्टिनेंट जनरल एसएस मेहता

पश्चिम वैश्विक प्रवाह में व्यवधान की असल कीमत व्यवस्था एवं ज़िंदगियां चुका रही हैं। होर्मुज में नाकाबंदी का असर आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के चलते ऊर्जा (पैट्रोल) व खाद्यान्न की कीमतों पर हो रहा है। जिसका असर महंगाई के रूप में आमजन के जीवन पर ही पड़ेगा। एक ऐसी साझी वैश्विक स्वचालित रूपरेखा की जरूरत है जिसके आवाजाही का सतत बने रहना जरूरी है।

वैश्विक प्रवाह यानी मुक्त आवाजाही में व्यवधान पड़ता है, तो इसका असर नाकाबंदी वाले बिंदु या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। दूर तक फैलता है। तेल से लेकर भोजन और रोज़ी-रोटी तक, इसकी कीमत व्यवधान वाली जगह से सुदूर क्षेत्रों को भी सहनी पड़ती है। जिस आवाजाही का सतत बने रहना जरूरी है उसके लिए हर बार वार्ता करने की जरूरत क्यों पड़े। यह सततता नियमबद्ध हो न कि अपवादवश पुन: खोलना।

जब 'प्रवाह के नियम' की व्याख्या पहली बार द ट्रिब्यून में की गई, तो यह विचार बतौर सिद्धांत नहीं आया था। यह एक गैर-रूढ़िवादी किंतु सहजबोध से उत्पन्न धारणा थी, क्योंकि मछुआरा हर जगह मौजूद है, हर क्षेत्र में जहां जीवन-निर्वाह मुक्त आवाजाही पर निर्भर है। जहां सततता रही वहां स्थिरता कायम है, जहां इसमें बाधा बनी, व्यवस्था पर दबाव पड़ा। जब मुक्त प्रवाह में खलल पड़े तो ताकतवर में तकरार होता है, वहां भुगतना कमजोरों को पड़ता है। कीमत मछुआरे को चुकानी पड़ती है। फिर, होर्मुज़ स्ट्रेट में, दुनिया ने उस कोताही की कीमत भुगती, जब आवाजाही नियमों की रूपरेखा तय करने से मुंह चुराया। व्यवधान पुन: बना, त्वरित परिणाम भी। बाज़ार में वस्तुओं की कमी हो गई। बीमा कंपनियां हिचकिचाने लगीं। आपूर्ति श्रृंखला लड़खड़ा गई। कुछ ही दिनों में, राष्ट्र जुटे, संधि या गठबंधन के तहत नहीं, बल्कि निर्भरता वश। यूके-फ्रांस की अगुवाई में एक प्रयास होने लगा, बतौर एक युद्धकालीन गठबंधन नहीं बल्कि जल परिवहन सुचारू रखने हेतु सुरक्षात्मक प्रबंधन के रूप में। सुरक्षा प्रदाता पोत साथ भेजने की बात चली। अपने नौसैन्य जहाज और सैनिक तैनात करने की पेशकश हुई। उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि जल मार्गों में मुक्त आवाजाही बनी रहे।

होर्मुज़ गठजोड़ कोई गठबंधन नहीं। स्वीकारोक्ति है। प्रवाह के नियम सीएलओसीस (सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन) का विकल्प नहीं। खंडित दुनिया में, जो मार्ग मुक्त रहना चाहिए हर बार खतरा आने पर उसको खुलवाने को समझौता वार्ता की नौबत क्यों बने? आवाजाही खुद अक्षुण्ण रहे। लेकिन उस दिन कुछ और हुआ। इस्लामाबाद में इस मुद्दे पर एक बैठक हुई थी। दोनों पक्ष वार्ता मेज पर आए। अपनी-अपनी स्थिति बताई व अड़े रहे। लेकिन कोई हल नहीं निकला। दुनिया ने वार्ता होते देखी पर उससे नई संरचना जन्म लेते नहीं। मौके को मिसाल में बदलना हाथ से निकल गया। यह सही होने की बात नहीं है। बल्कि इस बारे कि सही होने से क्या पता चलता है और क्या दायित्व उत्पन्न होते हैं। वही कुछ इस पल का अनुग्रह है। जो हुआ वह नियमों की रूपरेखा बनना नहीं था। यह दबाव में आकर बनाई एक कामचलाऊ व्यवस्था थी। फ्रांस और ब्रिटेन ने इक्यावन देशों को इसलिए इकट्ठा नहीं किया कि सिद्धांत ने यह करवाया बल्कि इसलिए कि कोताही की फौरी कीमत चुकानी पड़ रही है और नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन हो गया। वे संरक्षक ज़रूरत के चलते बने हैं। यह फ़र्क़ मायने रखता है। इस दिशा में प्रवाह का नियम सही साबित हुआ। लेकिन सिद्धांत और संरचना के बीच अंतर खतरनाक रूप से कायम है।

इंसान जो कीमत चुका रहा : इससे पहले कि हम जलडमरूओं और शीर्ष समझौता वार्ताओं पर फिर आएं, उनके बारे में सोचें कि जिन्हें व्यवधान की कीमत चुकानी पड़ती है। न रणनीतिकारों को, न मंत्रियों को, तेल के व्यापारियों को भी नहीं, यह तो केरल के किसी मछुआरे को सहनी पड़ रही है, जिसके लिए डीज़ल का दाम दोगुना हो गया। साहेल का वह किसान जिसकी खाद नहीं पहुंची। वियतनाम का कोई कारखाना मालिक जिसका निर्यात आर्डर जहाजरानी रूट बदल जाने पर खारिज हो गया। काहिरा का परिवार जो गेहूं की आवक में कमी से रोटी के बढ़े दाम देने पड़ रहे।

यह दुनिया में बार-बार दस्तक देने वाली सच्चाई है, जो प्रवाह सुचारु रहने पर निर्भर है, क्योंकि इसको सुरक्षित रखने के वास्ते नियमों की रूपरेखा नहीं बनाई गई। कोविड-19 को किसी पासपोर्ट की दरकार नहीं थी। यह उन्हीं राहों से फैला जिनसे सामान, पूंजी और लोग आवाजाही करते हैं। जब प्रवाह रुका, तो सबसे कम बचत वालों को सबसे पहले और ज़्यादा भुगतना पड़ा यानि दिहाड़ी मज़दूर, प्रवासी श्रमिक। व्यवधान उनका बनाया नहीं था। फिर भी भुगतना उन्हें ही पड़ा।

युद्ध का असर अब वहीं तक सीमित नहीं रहता जहां यह चल रहा होता है। यह आपूर्ति श्रृंखला में दाखिल हो जाता है। एक इलाके की जंग दूसरे इलाके के अन्न भंडार खाली करवा देती है। एक बंदरगाह पर हुए हमले से समूचे महासागरीय क्षेत्र में दाम बढ़ जाते हैं। आज युद्ध एक योजनाबद्ध व्यवधान है।

नाकेबंदी अपना फायदे खुलेआम घोषित नहीं करती। होर्मुज़ जलडमरू बंद होने के कुछ हफ्तों में ही, तेल का दाम बढ़कर सौ डॉलर प्रति बैरल होने का बोझ हरेक पैट्रोल पंप, हर ट्रांसपोर्ट लाइन , ढुलाई की जाने वाली हर चीज की कीमत पर पड़ा। केरल के मछुआरे ने इसके लिए वोट नहीं दिया था, फिर भी इसकी कीमत चुका रहा है। कोविड-जलवायु परिवर्तन-युद्ध-नाकाबंदी, इसका उदगम स्थल भिन्न, प्रभाव इनका एक जैसा। शुरुआत कुछ लोगों के फैसलों से होती है और हश्र करोड़ों-अरबों लोगों को प्रभावित करता है। हरेक की शुरुआत खबरों की सुर्खियों के रूप में होती है और परिणति घर खर्च पर पड़े बोझ के रूप में। हरेक रणनीति कमरे से शुरू होकर रसोई, खेत और कारखानों पर मार करती है। आम आदमी होर्मुज़ जलडमरू में नहीं रहता। वह यहां से निकलने वाले जलमार्ग के किसी छोर पर रहता है, उन कमरों में बैठकर लिए फैसलों के छोर पर जिनमें घुसने की उसे इज़ाजत नहीं, वह जिस व्यवस्था पर निर्भर है उसपर उसका वश नहीं। इसी वजह से प्रवाह का नियम रणनीतिक अंतर्दृष्टि बनकर नहीं रह सकता। इसमें सामाजिक सरोकार होना जरूरी है। जब प्रवाह में व्यवधान पड़ता है तो पहला नुकसान हमेशा उन लोगों का होता है, झटका झेलने की जिनकी सामर्थ्य सबसे कम होती है। होर्मुज़ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तेल की एक कीमत होती है। टैंकर ट्रैक किये जा सकते हैं। व्यवधान अपनी घोषणा खुद करता है। अगला संकट शायद न करे। एक कटा हुआ डेटा केबल किसी काम का नहीं। सेमीकंडक्टर की कमी चुपचाप बढ़ती है। एक खाद्यान्न मार्ग धीरे-धीरे बंद होता जाता है जबतक कि फ़िर से न खुले। होर्मुज़ के लिए 51 देश समय रहते एकजुट हुए। हो सकता है अगली बार, नाकाबंदी का बिंदु शायद इंतज़ार न करे।

जब प्रवाह फिर से रुक जाए: सिद्धांत और व्यवधान तले एक सरल सच दबा होता है। प्रत्येक व्यवस्था जो हमने बनाई है, संयुक्त राष्ट्र, लॉ ऑफ़ द सी, जलवायु संधि, व्यापार तंत्र, सब इस एक साझी धारणा पर टिके हैं: कि निरंतरता में इंसानियत का साझा हिस्सा है। इस धारणा को अनेक नाम दे रखे हैं। बहुआयामी व्यवस्था,नियमाधारित तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि। लेकिन इसका सबसे पुराना और ईमानदार नाम बस यही है: वैश्विक साझेदारी। फिर भी हम बर्ताव करते हैं मानो व्यवस्था को टुकड़ों में बांटकर सुरक्षित रख सकते हैं। हम अलग-अलग हिस्सों में समझौता करते हैं जबकि व्यवधान आसानी से उनके बीच विचरता है। संप्रभुता की भाषा सीमित रहती है। ज़िंदा रहने की सच्चाई अब सीमित नहीं रही।

युद्ध दर्शाता है कि अस्थिरता विस्तार लेती है। होर्मुज़ हमें याद दिलाता है कि जिस जलडमरू को शायद हम कभी न देख पाएं, वह उस रोटी की कीमत तय कर रहा है, जो हमें बारम्बार खरीदनी पड़ती है। प्रवाह का सिद्धांत शक्ति का सिद्धांत नहीं। यह एक-दूसरे पर निर्भरता स्वीकार करना है। निरंतरता के संरक्षक शक्ति के प्रहरी न होकर जन सेवक हैं। अब जबकि ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज़ को निरापद करने के लिए दुनिया को लामबंद कर रहे हैं, बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। व्यवधान के बोल निरंतरता की आवश्यकता को राह दे रहे हैं। जो कभी जबरदस्ती नियंत्रित था वह अब निर्भरता की मजबूरी है। फिर भी, जब अन्य राष्ट्र संकट की घड़ी में गठबंधन बना रहे हैं, हमारी भौगोलिकता और सभ्यता के गुण एक बड़ी भूमिका की ओर इशारा करते हैं, महज किश्तवार प्रतिक्रिया देने वाले न बनकर, हम एक भागीदार के रूप में, बल्कि अधिक टिकाऊ सिद्धांत के संभावित रचयिता के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिसमें व्यापार के निर्बाध प्रवाह को न केवल विशेषाधिकार बल्कि उसकी नींव माना जाए। हम न केवल भौगोलिक स्थिति के मुताबिक जलडमरुओं के मध्य स्थित हैं बल्कि ज़िम्मेदार भूमिका निभाने में भी। एक ऐसी दुनिया में जो अभी भी व्यवधान बनने पर ही सक्रिय होती है, हमारी विशिष्ट स्थिति उस विचार को स्वरूप दे सकती है कि प्रवाह की रूपरेखा इस प्रकार हो कि आवाजाही सदा मुक्त बनी रहे, न कि अपवाद वश खोलकर।

वह प्रवाह जिसका सतत बने रहना अनिवार्य है, उसमें व्यवधान न बनने पाए। एक समय तक आवाजाही मुक्त रही, पर फिलहाल नहीं है। अगली बार, पहली चेतावनी जलडमरू से न मिलकर, वह नीरवता देगी जहां कभी मछुआरे अपना जाल डाला करते थे। क्योंकि जब प्रवाह कायम रखने के लिए यदि हर बार मोलभाव करना जरूरी हो जाए, तो इसका मतलब है वह पहले से बाधित है।

लेखक सेना की पश्चिमी कमान के पूर्व कमांडर और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के संस्थापक ट्रस्टी हैं।

क्या शहरी व सम्पन्न महिलाएं ही फेमिनिज्म की आवाज हैं?

मेघना पंत

इंस्टाग्राम पर कुछ समय पहले पूजा (पुजारिनी प्रधान) का मामला छाया हुआ था। वे पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र की एक कंटेंट क्रिएटर हैं, जो गांव का जीवन और किताबों, फेमिनिज्म, समाज आदि पर कंटेंट बनाती हैं। उनकी लोकप्रियता जब तेजी से बढ़ी तो उनके कंटेंट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि इतने अच्छे वीडियो गांव की लड़की अकेले नहीं बना सकती, शायद उसके पीछे कोई एजेंसी या ब्रांड-सपोर्ट है।

धीरे-धीरे यह सिलेक्टिव फेमिनिज्म बनाम वास्तविक एम्पॉवरमेंट की बहस बन गई। पूजा के पक्ष में कहा जाने लगा कि क्या गांव की महिला अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकती और क्या यह सिर्फ शहरी महिलाओं का ही विशेषाधिकार है?

इस पूरे प्रसंग से एक बात बहुत दु:खद ढंग से साफ होती है कि 'टॉक्सिक फेमिनिज्म' भी 'टॉक्सिक मैस्क्युलिनिटी' जितना ही बुरा है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। बराबरी की लड़ाई में कहीं न कहीं हम दिखावे को ही मूल्य समझने की गलती कर बैठे हैं। कहीं-कहीं तो हम नारीवाद के असल मायनों से बहुत परे चले जाते हैं।

हमने स्त्रीत्व के ऐसे रूप को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जिसमें शोर तो बहुत है, लेकिन जो भीतर से खोखला है। जिसमें बगावत तो है, पर आत्मपरीक्षण नहीं। सच कहूं तो नाटकीयता, समझदारी से ज्यादा तेजी से फैलती है। मूर्खता जल्दी ध्यान खींचती है। और एल्गोरिदम्स को तो आक्रोश ही पसंद है।

लेकिन एक असहज कर देने वाला सवाल देश को खुद से ही पूछना चाहिए कि क्या गांवों से शहरों तक सिर्फ वही महिलाएं भारतीय नारीवाद की आवाज बनेंगी, जो साधन-सम्पन्न और सलीके से संजी-संवरी हों? क्योंकि सच्चाई यही है कि ज्यादातर भारतीय महिलाएं इंस्टाग्राम की दुनिया में नहीं जीतीं। दहेज के लिए हर घंटे उनकी हत्या और हर 13 मिनट में उनके साथ दुष्कर्म होता है। 20 करोड़ महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। वे ऐसे घरों में रहती हैं, जहां आज भी उन्हें पढ़ाई के लिए जूझना पड़ता है। दफ्तरों में समान वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और विवाह-संस्था में तो रोज वे आजादी की लड़ाई लड़ती हैं। उनके लिए नारीवाद दिखावे की चीज नहीं, अपने अस्तित्व की जंग है।

फिर भी, आज भारतीय स्त्री की नुमाइंदगी करने वाली सबसे बुलंद आवाजें अकसर समाज के छोटे से तबके से आती है, जो शहरी, अंग्रेजीदां, डिजिटल दुनिया की जानकार और 'एल्गोरिदम-अफ्रूव्ड' हैं। यह पूरी तरह गलत भी नहीं है। प्रतिनिधित्व बदलता रहता है। लेकिन यह प्रतिनिधित्व जब टॉक्सिक व्यवहार को तवज्जो दे, जब महिलाएं एक-दूसरे को नीचा दिखाकर खुश हों, तो हमें ठहरकर सोचने की जरूरत है। नारीवाद कभी भी तमाशा बनने के लिए नहीं था। न इसका मकसद महज ऐसी नूराकुश्ती बन जाना था, जहां यह साबित करने की होड़ हो कि कौन किसे महज 30 सेकंड में हरा सकता है।

जो हम देख रहे हैं, वह प्रगति नहीं, एक दिखावा है। उससे भी बदतर ये कि यह दिखावा उन्हीं व्यवस्थाओं को मजबूत करता है, जिन्हें नारीवाद खत्म करना चाहता है। पुरुषवादी इसे देखकर हंसते हैं। वे इसे और फैलाते हैं, क्योंकि पितृसत्ता के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कि महिलाएं सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें।

यह सही है कि भारतीय नारीवाद में हर तरह की आवाजों के लिए जगह है, भले वह गुस्से से भरी, बेबाक, उलझी-सी या सधी हुई हो। नारीवाद को सही होने के लिए 'अच्छा' होना जरूरी नहीं, लेकिन जिम्मेदार होना आवश्यक है। उसे बड़ी लड़ाई का एहसास होना चाहिए। और वह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

जब सार्वजनिक विमर्श में नारीवाद के नाम पर छोटी-छोटी ऑनलाइन लड़ाइयां हावी हो जाएं तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? इसका सबसे खतरनाक अर्थ यह है कि हम नारीवाद की व्यापकता को एक ब्रांड तक सीमित कर रहे हैं।

'सुविधा' को 'स्वच्छंदता' बनने से रोकने की पहल

डॉ. सुधिर कुमार

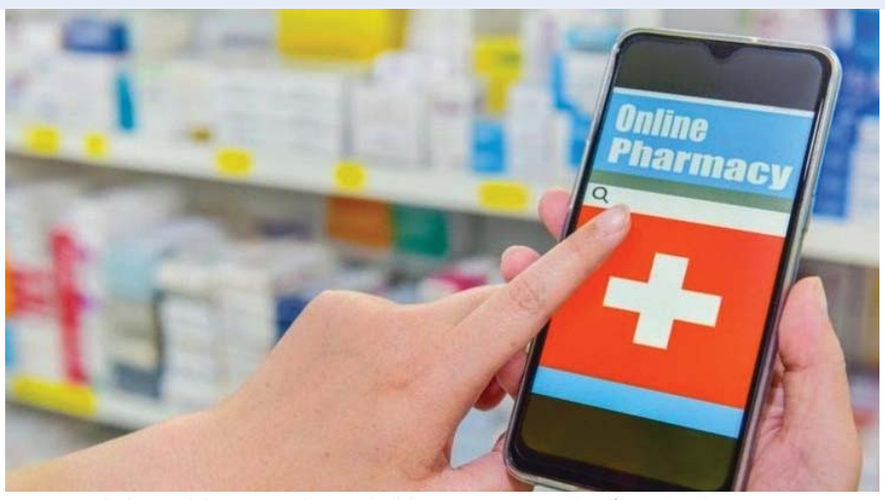

इस डिजिटल खेल का सबसे भयावह पहलू नशीली दवाओं और एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध दुरुपयोग है। अनिद्रा या तनाव से राहत पाने के लिए बिना डॉक्टरी परामर्श के मंगवाई गई नींद की गोलियां न केवल घातक 'लत' पैदा करती हैं, बल्कि विशेषज्ञ की निगरानी के अभाव में मानसिक संतुलन को भी पूरी तरह बिगाड़ सकती हैं।

बदलते दौर ने दवाओं की उपलब्धता को 'जरूरत' से 'सुविधा' में बदल दिया है। सामाजिक भरोसा अब स्मार्टफोन की एक 'क्लिक' में सिमट गया है। डिजिटल इंडिया की इस सुनहरी तस्वीर में दवाएं महज आधे घंटे में आपके दरवाजे पर पहुंच रही हैं। लेकिन कानून की कसौटी पर सवाल यह है कि क्या दवाओं की होम-डिलीवरी को पिज्जा ऑर्डर करने जितना ही सरल मान लेना चाहिए? 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' की जटिल कड़ियां और 'शेड्यूल-एच' दवाओं के जोखिम संकेत देते हैं कि ई-फार्मेसी की यह डगर जितनी चिकनी दिखती है, कानूनी और चिकित्सकीय सुरक्षा के लिहाज से उतनी ही पथरीली है।

ई-फार्मेसी कंपनियों का तर्क है कि वे तकनीक के जरिए दवाओं की उपलब्धता आसान बना रही हैं। वहीं, केमिस्ट का कहना है कि यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। असली संकट तब शुरू होता है जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना किसी वैध पर्चे के या पुराने, धुंधले पर्चों के आधार पर दवाएं बेची जाने लगती हैं। एक आम आदमी के लिए यह केवल 'सुविधा' है, लेकिन कानून की किताब में यह 'अपराध' की श्रेणी में आता है। जब आप बिना डॉक्टर की सलाह के खुद अपना डॉक्टर बनकर दवाएं मंगवाते हैं, तो आप अनजाने में एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस रहे होते हैं, जहां से निकलना मुश्किल है।

भारत में औषधियों का व्यापार 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' के अधीन है। चूंकि यह कानून इंटरनेट युग से पूर्व का है, इसलिए ई-फार्मेसी फिलहाल एक 'ग्रे एरिया' में सक्रिय हैं। कानून की स्पष्ट मर्यादा है कि 'शेड्यूल एच' और 'एच-1' श्रेणी की दवाएं बिना पंजीकृत डॉक्टर के वैध पर्चे के नहीं बेची जा सकतीं; ऐसा करना सीधे तौर पर विधिक उल्लंघन है। इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के पास पंजीकरण अनिवार्य होगा। इन प्रावधानों का उद्देश्य जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा को तकनीक के माध्यम से सुदृढ़ करना है।

इस डिजिटल खेल का सबसे भयावह पहलू नशीली दवाओं और एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध दुरुपयोग है। अनिद्रा या तनाव से राहत पाने के लिए बिना डॉक्टरी परामर्श के मंगवाई गई नींद की गोलियां न केवल घातक 'लत' पैदा करती हैं, बल्कि विशेषज्ञ की निगरानी के अभाव में मानसिक संतुलन को भी पूरी तरह बिगाड़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी प्रतिबंधित दवाओं का अवैध व्यापार आपको गंभीर कानूनी पचड़ों और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। वहीं, बिना पर्चे के एंटीबायोटिक्स का सेवन 'एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस' को जन्म दे रहा है, जिससे भविष्य में सामान्य संक्रमणों पर भी दवाएं बेअसर हो जाएंगी। पारंपरिक स्टोर एक 'मानवीय स्पर्श' और तत्काल जिम्मेदारी का अहसास कराते हैं, जहां फार्मासिस्ट पर्चे की भौतिक जांच कर उसके दुरुपयोग को रोकता है और मरीज को दवाओं के 'साइड इफेक्ट्स' के प्रति सचेत कर एक व्यक्तिगत विश्वास की कड़ी बनाता है।

इसके विपरीत, ई-फार्मेसी की दुनिया एल्गोरिदम पर टिकी है, जहां 'सुविधा' के साथ 'जोखिम' भी गहरे हैं। यहां सबसे बड़ी चिंता 'कोल्ड चेन मेंटेनेंस' (दवाओं के रखरखाव का तापमान) को लेकर है। यदि इंसुलिन जैसी जीवन-रक्षक दवाएं गोदाम से ग्राहक तक पहुंचने के दौरान निर्धारित तापमान पर न रखी जाएं, तो वे बेअसर होकर जानलेवा साबित हो सकती हैं।

सुरक्षा की पहली शर्त यह है कि उपभोक्ता केवल उन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें जो सरकार द्वारा पंजीकृत हों। विधिक दृष्टिकोण से, 6 महीने से अधिक पुराने पर्चे पर दवा मंगवाना न केवल स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा है, बल्कि इसे 'अवैध खरीद' की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। 'भारी डिस्काउंट' के प्रलोभन में गुणवत्ता से समझौता करना अपने जीवन को दांव पर लगाने जैसा है।

अक्सर ई-फार्मेसी कंपनियां खुद को महज 'बिचौलिया' बताकर पल्ला झाड़ लेती हैं। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने अब आम जन को एक सशक्त विधिक हथियार दिया है। यदि कोई कंपनी गलत या घटिया दवा की आपूर्ति करती है, तो उसे 'डेफिशिएंसी इन सर्विस' (सेवा में कमी) के आधार पर उपभोक्ता अदालत में चुनौती दी जा सकती है। क्षति की स्थिति में हर्जाना भरने व कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए बाध्य हैं। डिजिटल बिल और पैकेजिंग को साक्ष्य के रूप में संभाल कर रखना इस कानूनी लड़ाई में आपका सबसे बड़ा आधार है। आवश्यकता ई-फार्मेसी को प्रतिबंधित करने की नहीं, बल्कि 'सुविधा' को 'स्वच्छंदता' बनने से रोकने की है।

लेखक कुरुक्षेत्र विवि के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।

बेचारा रसगुल्ला तो पिछड़ गया जी

अगर वह बर्फी से, कलाकंद से भी पिछड़ता तो भी बात समझ में आती। लेकिन यहां तो झालमुड़ी ने रसगुल्ले को पछाड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसे करोड़ों लोगों ने सर्च किया और उसके लिए करोड़ों व्यूज आ गए।

यूं तो रसगुल्ला चाहत की चीज है, प्रेम करने की चीज है, लेकिन इन दिनों आप चाहें तो उसके साथ सहानुभूति भी प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि जो रसगुल्ला हमेशा ही दूसरी मिठाइयों पर भारी पड़ता रहा, उनसे आगे निकलता रहा, उन्हें पछाड़ता रहा, वही रसगुल्ला इधर दस रुपये की झालमुड़ी से पिछड़ गया है। वह अगर बंगाल के संदेश से पिछड़ता, वह रसमलाई से पिछड़ता, गुलाब जामुन से भी पिछड़ता, यहां तक कि अगर वह बर्फी से, कलाकंद से भी पिछड़ता तो भी बात समझ में आती। लेकिन यहां तो झालमुड़ी ने रसगुल्ले को पछाड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसे करोड़ों लोगों ने सर्च किया और उसके लिए करोड़ों व्यूज आ गए। जो रसगुल्ला बंगालियों के दिल के इतने करीब था, वह दस रुपये की झालमुड़ी से पिछड़ गया।

हालांकि, झालमुड़ी भी बंगालियों के दिल के बहुत करीब है। लेकिन बंगालियों ने उन्हें आमने-सामने कभी नहीं खड़ा किया। लेकिन मोदीजी ने कर दिया। वे तो परिवार के लोगों को आमने-सामने खड़ा कर देते हैं। जलकुकड़े तो उन पर आरोप लगाया ही करते हैं कि वे तो भाई-भाई को आमने-सामने खड़ा कर दें। बस उनके सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सच है कि इधर रसगुल्ला झालमुड़ी से पिछड़ गया है। उसका रस, उसकी चाशनी, उसकी नर्म-स्पंजी बनावट, मुड़ी यानी मुरमुरों, सरसों के तेल और हरी मिर्च के तीखेपन से हार गयी। बंगालियों को समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या हो गया। एक बार जब ओडिशा वालों ने रसगुल्ले पर अपना दावा ठोक दिया था तो, बंगाली जी जान से उनसे लड़े थे और रसगुल्ले को उसी तरह से बंगाल ले गए थे, जैसे कोई ट्रॉफी जीतकर ले जाता है। लेकिन झालमुड़ी पर किसी ने दावा किया ही नहीं। वह तो बंगालियों की ही है। अलबत्ता थोड़ा बहुत बिहार वाले उस पर दावा कर सकते हैं। हम तो वैसे भी लड्डू जलेबी वाले लोग हैं। झालमुड़ी बजाय यहां तो भुने हुए चने ही चलते हैं और वह भी बस आठ बजे वाली डोज के लिए चाहिए। रसगुल्ला और झालमुड़ी अमीर और गरीब किस्म के दो वर्ग हैं। रसगुल्ला अभिजात्यवर्गीय है। झालमुड़ी सर्वहारा है। रसगुल्ला सेलिब्रिटी मिठाई है। लेकिन मोदीजी ने झालमुड़ी को सेलिब्रिटी बना दिया। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है कि मोदीजी ने झालमुड़ी खाई और वह हिट हो गयी। मोदीजी तो वहवाली मशरूम भी खाते हैं, जिसे लेकर जलकुकड़े न जाने क्या-क्या कहते रहते हैं। पर वह तो हिट नहीं हुई। उसके तो करोड़ों व्यूज नहीं आए। मोदीजी तो खिचड़ी, ढोकला, फाफड़ा वगैरह भी खाते हैं। पर वे ऐसे कहां हिट हुए। ऐसे में यह झालमुड़ी की अपनी खासियत होगी जो वह इतनी हिट हुई। नहीं क्या?

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

आयुक्त ने एसएलआरएम सेंटरों का किया निरीक्षण

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पाण्डेय ने शहर के विभिन्न एसएलआरएम सेंटरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि जिन एसएलआरएम सेंटरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि शहर से निकलने वाले कचरे का समय पर और व्यवस्थित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। आयुक्त ने बायोगैस प्लांट को पुन: प्रारंभ कराने के निर्देश दिए, ताकि जैविक कचरे का बेहतर उपयोग किया जा सके। मुख्य कार्यालय स्थित सुलभ शौचालय का भी संधारण कार्य कराने कहा गया है।

शिकायत पर निगम ने चलाया जेसीबी- अतिक्रमण ध्वस्त

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 02 वैशाली नगर अंतर्गत नाली के उपर किये गये अवैध अतिक्रमण को निगम की टीम ने ध्वस्त किया। स्थानीय निवासियों द्वारा जनदर्शन में शिकायत दर्ज किया गया है कि कुछ मोहल्लेवासी अपने घरो के सामने गाड़ी निकालने एवं चढ़ाने के लिए रैम्प बनाए हैं, जिसके कारण गली में चलने फिरने में परेशानी होती थी। निगम आयुक्त राजीव पाण्डेय को प्राप्त सूचना के आधार पर जोन-2 का राजस्व विभाग एवं बेदखली की संयुक्त टीम द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। स्थल पर पाया गया कि कुछ लोगों द्वारा नाली के उपर अतिक्रमण कर रैम्प बनाया गया है, जिससे गली सकरा हो गया है और आवागमन में असुविधा हो रही है। संयुक्त टीम ने पंचनामा तैयार कर जेसीबी के माध्यम से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। साथ ही उनको समझाइश दी गई की दुबारा निर्माण करने पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जाएगा।

फोरलेन सड़क निर्माण के लिए निगम की बड़ी कार्रवाई, कब्जा और अतिक्रमणों पर गिरी गाज

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। यातायात को सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जेल तिराहा से पुलगांव रोड होते हुए मिनी माता चौक तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण कार्य को गति देने के लिए अतिक्रमण हटाने की मुहिम प्रारंभ कर दी गई है।

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत न केवल चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाना है, बल्कि सड़क के दोनों ओर सुदृढ़ ड्रेनेज सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए मार्ग में आने वाले सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाना आवश्यक है।

निगम द्वारा पूर्व में सर्वे कर चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी, जिसके आधार पर अब अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब तक 112 से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमाया जा चुका है, जिसमें उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को निगम के अतिक्रमण दस्ता द्वारा पुलगांव चौक के आसपास कार्रवाई करते हुए नालियों पर किए गए पक्के निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे और कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए निगम द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया है। सहायक अभियंता गिरीश दीवान को टीम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, उपअभियन्ता विनोद मांझी, तोड़ूदस्ता प्रभारी ईश्वर वर्मा एवं परमेश्वर कुमार सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर निगम के कार्य में सहयोग करें, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आवारा मवेशियों के विरुद्ध निगम का विशेष अभियान शुरू

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा में मुख्य मार्गों एवं बाजार क्षेत्रों में आवारा मवेशियों के कारण हो रही असुविधा और संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए निगम प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है। निगम की टीम मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे मवेशियों को दो शिफ्टों में पकड़ रही है। अतिक्रमण टीम ने आज आमदी मंदिर के पीछे सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर काऊ कैचर वाहन की सहायता से मवेशियों को सुरक्षित रूप से पकड़ा। रात के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पकड़े गए मवेशियों को रेडियम पट्टी पहनाई जा रही है, ताकि अंधेरे में भी वे स्पष्ट रूप से दिखाई दें और वाहन चालक सतर्क हो सकें। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बताया कि नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर निगम द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

फील परमार्थ टीम ने की राज्यपाल से मुलाकात; दी गतिविधियों की जानकारी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज फील परमार्थ आश्रम, भिलाई के संस्थापक अमित राज ने सौजन्य मुलाकात की। उन्हें आश्रम की गतिविधियों एवं समाजसेवा से जुड़े कार्यों की जानकारी प्रदान की।

आश्रम द्वारा सड़कों पर लावारिस अवस्था में घूम रहे बुजुर्गों तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का रेस्क्यू कर उन्हें आश्रम में आश्रय दिया जाता है। वहां उनके उपचार, देखभाल, भोजन तथा आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाती है।

उन्होंने बताया कि अब तक आश्रम के माध्यम से 208 लोगों को राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्तमान में आश्रम में 94 लोग निवास कर रहे हैं, जिनकी नियमित देखरेख की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल से आश्रम का भ्रमण करने का आग्रह भी किया।

राज्यपाल ने आश्रम द्वारा किए जा रहे मानवीय एवं सेवा कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी पहल बताया।

उल्लेखनीय की राज्यपाल द्वारा इस संस्था को पूर्व में 2 लाख रुपए का स्वेछानुदान भी प्रदान किया गया है। इस अवसर पर आश्रम के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

चित्रगुप्त प्रकटोत्सव पर दुर्ग में निकली भव्य शोभायात्रा

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। कायस्थ सभा दुर्ग द्वारा भगवान चित्रगुप्त के प्रकटउत्सव के अवसर पर कसारीडीह स्थित कायस्थ सभा भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें दुर्ग भिलाई के लगभग 200 कायस्थ परिवारों ने हिसा लिया। शोभा यात्रा में घोड़ों से सुसज्जित रथ में अक्षत श्रीवास्तव भगवान श्री चित्रगुप्त के प्रतिरूप के रूप में उपस्थित थे।

कायस्थ सभा दुर्ग के डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि चित्रगुप्त भगवान का प्रकटीकरण ब्रम्हा जी की काया से हुआ इसीलिये इस वर्ग के लोगों को कायस्थ कहा जाता है। शोभा यात्रा के पूर्व चित्रगुप्त मंदिर में भगवान का पूजन एवं अभिषेक हुआ जिसमें मुख्य जजमान के रूप में जेसीआई संतोष सिन्हा एवं रानू सिन्हा उपस्थित थी।

कायस्थ सभा दुर्ग के अध्यक्ष राजेश महावीर प्रसाद श्रीवास्तव एवं सचिव सुमीत श्रीवास्तव ने बताया कि भव्य शोभा यात्रा केलाबाडी, सुराना कॉलेज होती हुई सांई बाबा मंदिर से प्रवेश कर वापस कायस्थ सभा भवन पहुंची। उपस्थित लगभग 200 से अधिक कायस्थ जनों ने भगवान चित्रगुप्त की आरती भी की। कायस्थ सभा के सचिव श्री हर्षवर्धन श्रीवास्तव बताया कि यात्रा में 90 वर्षीय नन्दू लाल श्रीवास्तव तथा 87 वर्षीय राधेष्याम श्रीवास्तव भी शामिल थे। दोनों ने शोभा यात्रा के दौरान नृत्य भी किया।

कायस्थ समाज महिला मण्डल की उपाध्यक्ष सरोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकटोत्सव में महिला मण्डल का विशेष योगदान रहा। शोभा यात्रा में बढ़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य गरबा, भांगड़ा तथा हिन्दी लोक नृत्य की सामूहिक रूप से प्रस्तुति दी। इस अवसर पर डॉ. सरिता प्रशांत श्रीवास्तव, श्रद्धा सुमीत श्रीवास्तव, पूनम अनिल श्रीवास्तव, अलका संजीव ब्यैहार, सुरेन्द्र खरे, राकेश कुमार श्रीवास्तव, रश्मि सुधीर श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, संजय वर्मा, रूचि सकसेना एवं पी.वी. सकसेना, अंजना एवं समर्थ श्रीवास्तव, आदि ने भागीदारी दी।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 152वीं तिमाही समीक्षा बैठक संपन्न, फ्लिप बुक का विमोचन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। बीएसपी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 152वीं तिमाही समीक्षा बैठक 4 अप्रैल 2026 को कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई इस्पात संयंत्र, पवन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

सर्वप्रथम अमूल्य प्रियदर्शी ने पुस्तक भेंट कर कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार एवं महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन) जेएन ठाकुर का स्वागत किया। राजीव कुमार ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई-दुर्ग' को वर्ष 2024-25 के लिए 'नराकास राजभाषा, सम्मान' तृतीय पुरस्कार प्राप्ति की बधाई दी व कहा कि 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई-दुर्ग' का संयोजक संस्थान होने के नाते यह उपलब्धि भिलाई इस्पात संयंत्र लिए विशेष गौरव का विषय है। इस उपलब्धि का श्रेय सभी के प्रयासों को जाता है।

इस अवसर पर पवन कुमार द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र की हिंदी गृह पत्रिका 'भिलाई भाषा भारती' के 'संयंत्र विशेषांक' तथा 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई-दुर्ग' की पत्रिका 'महानदी' के 'ऑपरेशन सिंदूर' विशेषांक के ई-संस्करण का 'फ्लिप-बुक' के रूप में विमोचन किया गया।

कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार ने कहा कि, हिंदी में कार्य करने में प्रत्येक कार्मिक की भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है। पत्रिका 'भिलाई भाषा भारती' तथा 'महानदी' के 'फ़्लिप-बुक' के रूप में ई-संस्करण की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि, केवल एक लिंक के माध्यम से संपूर्ण पत्रिका उपलब्ध होना सराहनीय है। इससे न केवल पत्रिकाओं की अधिकाधिक पाठकों तक पहुँच बढ़ेगी, वरन बहुमूल्य काग़ज़ की भी बचत होगी, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान होगा। हिंदी भाषा की इन पत्रिकाओं के माध्यम से लोग हिंदी से अधिक से अधिक जुड़ सकेंगे।

संचालन उप प्रबंधक (जनसंपर्क) सुश्री शालिनी चौरसिया ने किया। उप प्रबंधक (संपर्क व प्रशासन - राजभाषा) जितेन्द्र दास मानिकपुरी ने विगत बैठक की कार्यसूची का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तत्पश्चात आगामी तिमाही की कार्यसूची का वाचन कर शत-प्रतिशत हिंदी में पत्राचार करने वाले विभागों का उल्लेख कर आगामी तिमाही की कार्यसूची का वाचन तथा आभार प्रदर्शन किया।

दुर्ग के दादा दादी पार्क में लकवाग्रस्तों की फिजियोथेरेपी

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत महापौर अलका बाघमार ने लोक कर्म प्रभारी देवनारायण चन्द्राकर, शेखर चन्द्राकर के साथ दादा-दादी नाना-नानी पार्क स्थित लकवा पॉइंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां एक्सरसाइज कर रहे लकवा (पैरालिसिस) मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली।

महापौर ने मौके पर उपस्थित लोगों से चर्चा करते हुए जाना कि नियमित व्यायाम और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने मरीजों के परिजनों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि निगम स्तर पर हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। निरीक्षण के दौरान महापौर ने लकवा मरीजों के लिए आवश्यक एक्सरसाइज सामग्री एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु 5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सामग्री की उपलब्धता और व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि मरीजों को उसका लाभ मिले तथा किसी प्रकार की असुविधा न हो।

महापौर ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे नागरिकों को सहयोग प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि लकवा मरीजों के पुनर्वास और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ऐसे केंद्रों का सशक्त होना बेहद आवश्यक है।

उन्होंने आगे कहा कि नियमित व्यायाम, सकारात्मक वातावरण और उचित संसाधनों के माध्यम से लकवा मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दिलाने में मदद मिल सकती है। नगर निगम इस दिशा में लगातार प्रयासरत रहेगा।

रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर रेलवे ने किया दीपक का सम्मान

भिलाई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल एवं ऑल इंडिया एससीएसटी इलेक्ट्रिक लोको शेड (ईएलएस) चरोदा शाखा ने विगत दिनों बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की जयंती का आयोजन किया। इस दौरान ईएलएस चरोदा में पदस्थ रेलवे कर्मी दीपक कुमार को रक्तदान के माध्यम से मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि दीपक कुमार न सिर्फ स्वयं रक्तदान करते हैं बल्कि दूसरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करते रहे हैं।

विश्व मलेरिया दिवस पर निकाली जागरूकता रैली

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर शासन की मंशानुरूप एवं आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के निर्देशों के परिपालन में शहर को मलेरिया मुक्त बनाने हेतु वृहद जागरूकता अभियान चलाया गया। निगम के जोन-1 (नेहरू नगर) के अंतर्गत वार्ड-5 कोसानगर (राधाकृष्ण मंदिर के पीछे की बस्ती) तथा जोन-3 (मदर टेरेसा नगर) के अंतर्गत वार्ड-33 संतोषी पारा (हुडको क्वार्टर) में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से आम नागरिकों को मलेरिया रोधी नारों के जरिए बीमारी से बचाव के उपाय बताए गए। अभियान का मुख्य संदेश हर बुखार की जांच - मलेरिया की पहचान रहा। समझाया गया कि घरों के आसपास जल जमाव न होने दें। मच्छरों का प्रजनन रोकने में सहयोग करें।

जल संरक्षण में नवाचार, 300 ग्राम पंचायतों में आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिले के सभी 300 ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन ग्राम सभाओं में 'नवा तरिया आय के जरिया', जनगणना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारियों को ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए थे, जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली।

ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'संपदा' ऐप में परिसंपत्तियों का अपलोड, 'मोर गांव मोर पानी' महाअभियान के अंतर्गत जल संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन, तथा 'नवा तरिया आय के जरिया' जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जनगणना के लिए स्वयं गणना पत्रक भरने की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित जानकारियों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया।

कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह द्वारा पूर्व में ही सभी ग्राम पंचायतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। निर्देशानुसार ग्राम सभाओं में जनप्रतिनिधियों एवं सम्मानित नागरिकों को आमंत्रित कर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की गई।मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि ग्राम सभाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' अंतर्गत लखपति दीदियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल संरक्षण एवं आजीविका बढ़ाने के उपायों पर ग्रामीणों से सुझाव लिए गएइसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में संचालित ोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत एक अभिनव पहल की गई है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन की दीवारों पर गांव के जलस्तर (वॉटर लेवल) की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है, जिससे आम नागरिक अपने क्षेत्र के भू-जल स्तर से अवगत हो सकें।'जल-दूत' मोबाइल ऐप के माध्यम से जलस्तर से संबंधित आंकड़े संकलित कर पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं।

क्वांटम तकनीक से पता चलेगा भूकंप, जमीन के अंदर छिपा तेल

भिलाई। भविष्य में जमीन के अंदर छिपे तेल-गैस का पता लगाना हो, भूकंप की सटीक जानकारी पहले से चाहिए हो या अंतरिक्ष में हुई किसी दुर्घटना की सूचना तुरंत पृथ्वी तक पहुंचानी हो, यह सब अब क्वांटम तकनीक के जरिए संभव हो सकता है। प्रोफेसर सुधन्वा पात्रा के नेतृत्व में किए गए इस शोध को अंतरराष्ट्रीय जर्नल फिजिकल रिव्यु डी (2026) में प्रकाशित हुआ है। शोध का मुख्य कार्य पीएचडी छात्रा राजरुपा बनर्जी ने किया। शोध पीएचडी छात्रा राजरुपा बनर्जी ने पीके पाणिग्रही (एसओए यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक) और हिरनमया मिश्रा (नेशनल इंस्ट्रीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च में विज़िटिंग प्रोफेसर) के सहयोग से किया है।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास-खबर

अनुसूचित जाति बालक प्री-मेट्रिक छात्रावास में शिक्षा, अनुशासन और कैरियर मार्गदर्शन से संवरता भविष्य

रायपुर। अनुसूचित जाति बालक प्री-मेट्रिक छात्रावास मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के बदौलत सफलता की नई पहचान बन रहा है। महासमुंद जिले के बागबाहरा में निर्मित छात्रावास भवन के छात्र सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देख रहे हैं और उन्हें साकार करने में जुटे हैं। इस वर्ष यहां के 7 छात्रों का चयन प्रतिष्ठित प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए हुआ है। एक ही छात्रावास से इतने छात्रों का चयन होना एक बड़ी उपलब्धि है और यह यहां की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दर्शाता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के सभी आश्रम छात्रावासों में विद्यार्थियों के शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन और कैरियर मार्गदर्शन के क्षेत्र में भी विशेष पहल की जा रही है। विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आश्रम छात्रावासों के मूलभूत सुविधाओं के साथ ही बच्चों के भविष्य को संवारने उनके नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे है। वहीं प्रोजेक्ट संकल्प के माध्यम से बच्चों के नैतिक, व्यवहारिक और सांस्कृतिक शिक्षा देने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सफलता भी सामने आयी है इसमे लगातार छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं विषय विशेषज्ञों के जरिए बच्चों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छात्रावास अधीक्षक मनोज चौधरी के मार्गदर्शन में यहां पढ़ाई का स्तर लगातार बेहतर हुआ है। यह छात्रावास पढ़ाई के साथ छात्रों के कैरियर निर्माण में भी भूमिका निभा रहा है।

छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक 29 अप्रैल को

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक 29 अप्रैल 2026 को अपरान्ह साढ़े तीन बजे से मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की जाएगी। इस आशय का पत्र आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री एवं जनजातीय सलाहकार के परिषद के उपाध्यक्ष श्री रामविचार नेताम सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं परिषद के सभी सदस्य उपथित रहेंगे। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में (दिनांक 11 मार्च 2025) के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा भी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।

सीबीएसई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में केवल एनसीईआरटी की किताबें ही मान्य

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियो को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अब एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से ही अध्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभिभावकों और छात्रों पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें और वर्कबुक खरीदने के लिए दबाव डालने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सख्त हो गए हैं। अप्रैल 2026 में जारी आदेशों के अनुसार निजी स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबें ही अपनाने के निर्देश दिए गए हैं और निजी दुकानों से किताबें खरीदने की बाध्यता खत्म करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन का उद्देश्य पालकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाना और शिक्षा को सुलभ बनाना है। मुख्य सचिव ने समस्त कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि निजी विद्यालयों द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें क्रय करने हेतु विद्यार्थियों एवं पालकों को बाध्य नहीं किया जाए। निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य करने पर सख्त कार्रवाई करें। सीजी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों में पहली से 10 वीं तक एससीईआरटी की छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से प्रकाशित पुस्तकें विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रदाय की जाती हैं। पुस्तकें खरीदने हेतु बाध्य करना पूर्णत: प्रतिबंधित है।

50 हजार से अधिक परिवारों के 'अपना घर' का सपना हुआ साकार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सफल क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 50 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जन मन योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है, जिसके माध्यम से जिले के हजारों जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत मिली है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 50 हजार 44 परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं। जिला प्रशासन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कुल 781.13 करोड़ रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की

गई, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और कार्यों में तेजी आई।

क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मस्तूरी विकासखंड 14 हजार 973 आवासों के साथ जिले में शीर्ष पर रहा। इसके बाद बिल्हा में 13 हजार 762, कोटा में 11हजार 205 और तखतपुर में 10 हजार 104 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया। यह आंकड़े न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाते हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी साबित करते हैं।

इस सफलता के पीछे 'नारी शक्ति' की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिले में 113 महिलाओं को 'रानी मिस्त्री' के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी दी गई, जिससे वे आत्मनिर्भर बनीं। वहीं 331 महिलाओं को 'डीलर दीदी' बनाकर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी। इसके अलावा 2,231 महिलाओं को शटरिंग सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आई और महिलाओं की आय के नए स्रोत विकसित हुए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक जिले ने कुल एक लाख 3 हजार 873 आवास पूर्ण कर छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिले की मजबूत कार्ययोजना, सतत मॉनिटरिंग और जनसहभागिता का परिणाम है। इस योजना का मानवीय पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

ग्राम डारसागर की झांगली बैगा और ग्राम नेवसा की कैलाशा बाई जैसी हितग्राही, जो वर्षों से कच्चे मकान में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थीं, आज पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। उनके लिए यह केवल एक मकान नहीं, बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य का प्रतीक है।

कलेक्टर बिलासपुर ने इस उपलब्धि को जिले के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि ये 50 हजार से अधिक घर केवल ईंट और सीमेंट की संरचनाएं नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान और सुरक्षा की नींव हैं। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि भविष्य में भी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी।

कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल की मौजूदगी में डीएमएफशासी परिषद की बैठक

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पेयजल पर विशेष फोकस

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि डीएमएफ निधि का अधिकतम उपयोग जनहित के प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन और स्वच्छता में किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व में स्वीकृत कार्यों को समयसीमा में पूर्ण किया जाए और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो। साथ ही उन्होंने सुपर 30 कोचिंग योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने पर विशेष जोर दिया।

मंत्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति तथा कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास अजीत वसंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट अंबिकापुर सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई और कहा कि सभी विभाग अपने प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर तैयार करें, ताकि डीएमएफ राशि का प्रभावी और जनहितकारी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि नए नियमों के अनुरूप पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करने हेतु विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि डीएमएफनिधि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और नियमानुसार करते हुए जिले के समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव डीएमएफ श्री विनय अग्रवाल ने वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक विभिन्न सेक्टरों में स्वीकृत, पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इसमें उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल कल्याण तथा स्वच्छता से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए डीएमएफ अंतर्गत ऑडिट कार्य के अनुमोदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से जिले के विकास के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया।

बैठक में लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, डीएफओ अभिषेक जोगावत सहित शासी परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने फीस विनियमन अधिनियम का कड़ाई से पालन कराएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य के कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा पालकों से उनके पाल्यों के अध्यापन हेतु नियम विरुद्ध शुल्क वसूला जा रहा है। मुख्य सचिव विकासशील इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को 'छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020' का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि पालकों के हितों की रक्षा एवं शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए फीस विनियमन अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

राज्य में 26 अगस्त 2020 से प्रभावशील इस विधेयक के अध्याय-2 की कंडिका-3 के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय में विद्यालय फीस समिति का गठन अनिवार्य है। यह समिति प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष के शुल्क से अधिकतम 8 प्रतिशत तक ही शुल्क वृद्धि का अनुमोदन कर सकेगी। 8 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि की स्थिति में जिला फीस समिति से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक निजी विद्यालय में फीस विनियमन समिति को तत्काल क्रियाशील बनाया जाए। निजी विद्यालयों से समन्वय एवं नियंत्रण के लिए नोडल प्राचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा नोडल प्राचार्य विद्यालय शुल्क विनियमन समिति के सदस्य भी होते हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शुल्क विनियमन समिति के सदस्य सचिव होते हैं। नियम विरुद्ध शुल्क वृद्धि किये जाने पर संबंधित निजी विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

बस्तर मुन्ने कार्यक्रम से हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोंडागांव। प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा बस्तर मुन्ने कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत संतृप्तता शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य एनसीईआर सर्वेक्षण में नियद नेल्लानार के तहत चिन्हित 31 जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित परिवारों को शत-प्रतिशत लाभ प्रदान करना है। इसी क्रम में जनपद पंचायत बड़ेराजपुर में नोडल अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम के प्रभावी संचालन एवं व्यक्तिमूलक योजनाओं के शत-प्रतिशत सेच्यूरेशन पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत, क्लस्टर एवं विकासखण्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण कार्य जारी है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के संभावित लाभार्थियों का चिन्हांकन कर उन्हें त्वरित लाभ प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम चरण में ग्राम पंचायतों को योजनावार लक्ष्य, प्रचार-प्रसार सामग्री, पात्रता मापदंड एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मैदानी अमले को हितग्राहियों की सूची प्रदान की गई है। द्वितीय चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर सर्वेक्षण के आधार पर पात्रता परीक्षण एवं योजनाओं का लाभ वितरण किया जाएगा। सर्वेक्षण से छूटे परिवारों का भी पंजीयन कर नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) से एक सप्ताह तक ग्राम सभाओं का आयोजन कर तीन प्रमुख सामुदायिक कार्यों का चयन किया जाएगा। अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर शासन को प्रेषित किया जाएगा।

तृतीय चरण में ग्राम पंचायत स्तर के लंबित प्रकरणों का क्लस्टर स्तर पर शिविर आयोजित कर निराकरण किया जाएगा। चतुर्थ चरण में क्लस्टर स्तर के लंबित मामलों का विकासखण्ड स्तर पर जिला अधिकारियों की उपस्थिति में समाधान किया जाएगा तथा शिविरों के प्रभाव का मूल्यांकन भी किया जाएगा। पांचवें एवं अंतिम चरण में सभी शिविरों की समीक्षा, प्रभाव का आंकलन एवं थर्ड पार्टी फीडबैक लिया जाएगा, जिससे कार्यक्रम की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

शासन श्रमिकों के मेहनत की कीमत समझती है, उन्हें योजनाओं का लाभ दे रही हैः सांसद भोजराज नाग

6263 श्रमिकों के खाते में 02 करोड़ 96 लाख रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जिला प्रशासन बालोद और श्रम विभाग के संयुक्त प्रयासों से आज जिले के हजारों श्रमिकों में खुशियों का संचार हुआ। जिला मुख्यालय बालोद में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में जिले के विकास की रीढ़ माने जाने वाले हजारों श्रमिकों को करोड़ों रुपये की सौगात दी गई। श्रमिक सम्मेलन में जिले भर से पहुँचे पंजीकृत श्रमिकों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद भोजराम नाग थे।

श्रमिक सम्मेलन में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 6263 श्रमिकों के बैंक खाते में 02 करोड़ 96 लाख 15 हजार 740 रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना से 5513 श्रमिक, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना से 53 श्रमिक, मिनीमाता महतारी जतन योजना से 431 श्रमिक, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से 30 श्रमिक और मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से 236 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा उक्त योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को डेमो चेक प्रदान कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी गई। श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद भोजराज नाग ने कहा कि शासन श्रमिकों के पसीने की कीमत समझती है। हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, हर मोड़ पर सरकार आपके साथ खड़ी है। उन्होंने शासन द्वारा श्रमिकों में हित में लिए गए निर्णयों की भी विस्तृत जानकारी दी तथा सभी श्रमिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने प्रेरित किया। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब श्रमिकों के बच्चे भी मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पाकर ऊँचे सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्होंने सभी अपंजीकृत श्रमिकों से जल्द से जल्द पंजीयन कराने का आह्वान किया ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।

कार्यक्रम को विधायक कुंवर सिंह निषाद ने भी संबोधित किया और सभी श्रमिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा ने आभार प्रदर्शन किया तथा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

इस अवसर पर गुण्डरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर, नगर पालिका बालोद की अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती टेमरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

पंजीकृत रकबे के मुताबिक सभी किसानों को मिलेगी समय पर खादः रामविचार नेताम

खरीफ सीजन 2026 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आवंटित, काला बाजारी और जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्यवाही के निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका - इज़राइल और ईरान के बीच तनाव के बीच आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से आगामी खरीफसीजन 2026 के लिए छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार द्वारा 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आबंटित हुआ है। जिसमें यूरिया 7.25 लाख, डीएपी 3 लाख, एमओपी 80 हजार, एनपीके 2.5 लाख तथा एसएसपी 2 लाख मीट्रिक टन शामिल हैं।

वर्तमान में गोदामों एवं समितियों में लगभग 7.48 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी किसानों को पारदर्शिता के साथ पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद का आबंटन सुनिश्चित हो।

मंत्री नेताम ने बताया कि 30 मार्च की स्थिति में राज्य में कुल 7.48 लाख मीट्रिक टन उर्वरक स्टॉक में मौजूद है, जिसमें यूरिया 2,43,717 मीट्रिक टन, डीएपी 1,05,631 मीट्रिक टन, एनपीके 1,69,109 मीट्रिक टन, एमओपी 50,431 मीट्रिक टन और एसएसपी 1,78,657 मीट्रिक टन इस तरह कुल 7.48 लाख मीट्रिक टन खाद स्टॉक में मौजूद है।

मंत्री नेताम ने बताया कि पश्चिमी एशियाई संकट के चलते रासायनिक उर्वरकों की संभावित कमी को देखते हुए विभाग द्वारा किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत एनपीके 12:32:16, 20:20:0:13, हरी खाद, जैविक खाद और नैनो उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।

मंत्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार ने उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर उड़नदस्ता दल और निगरानी समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर उर्वरकों में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार ने रायपुर और दुर्ग संभाग के विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी खरीफ सीजन 2026 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से कहा है कि पीएम किसान पोर्टल से एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों के पंजीयन तेजी से पूर्ण कर लिया जाए। बीज एवं उर्वरक वितरण के लिए नई ई-वितरण प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए।

वही रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में हरी खाद, जैव उर्वरक और नील-हरित काई के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी और डायवर्जन रोकने के लिए जिलों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत दलहन और तिलहन फसलों के उपार्जन को भी प्राथमिकता में रखा गया है। उन्होंने हर जिले में सुगंधित धान की प्रजाति के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही दलहन-तिलहन फसलों तथा उद्यानिकी क्षेत्र में ऑयल पाम, मखाना और मसाला फसलों के विस्तार के निर्देश दिए हैं।

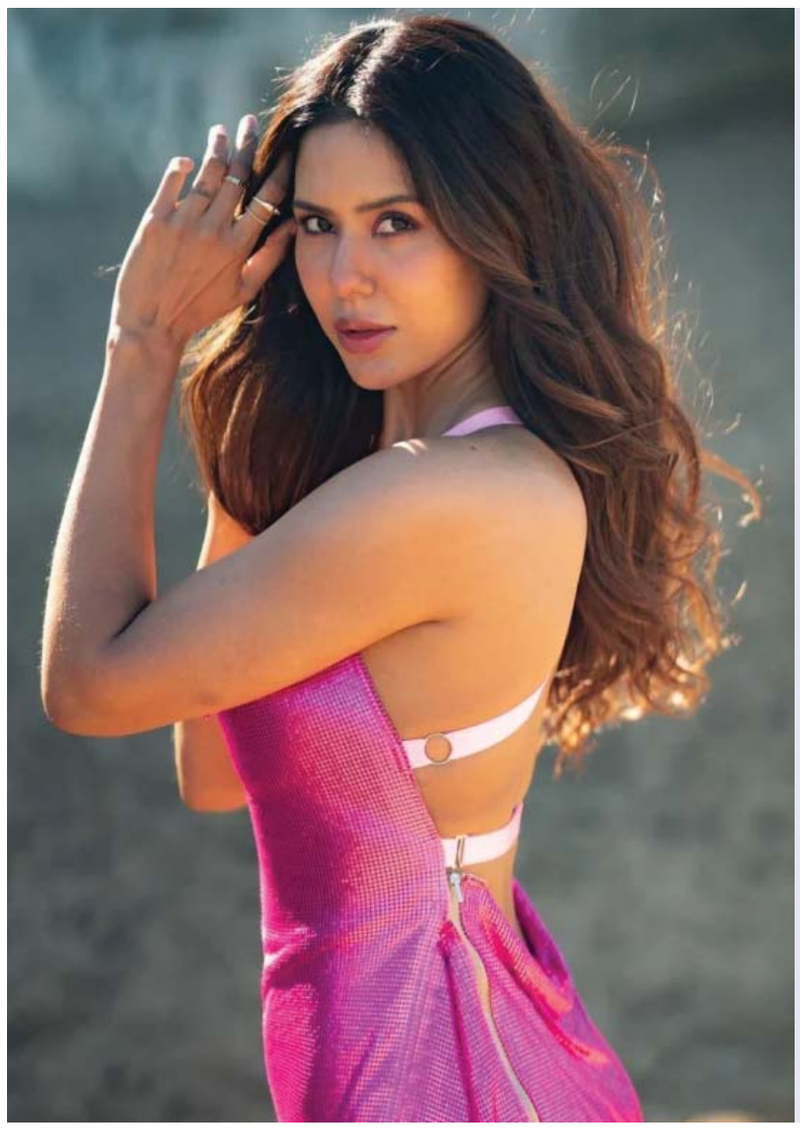

'मुझे पैपराजी से बात करना अच्छा लगता है'

सोनम बाजवा ने पैप्स कल्चर पर रखी राय; जैकलीन की सलाह को किया याद

अभिनेत्री सोनम बाजवा इन दिनों अपनी आगामी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'पिट सियापा' को लेकर चर्चाओं में हैं। इस फिल्म में सोनम प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। हाल ही में सोनम ने पैपराजी के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने बताया कि जब पैप्स उनसे फोटोज के लिए कहते हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है?

पैपराजी के सामने मैं हंसती रहती हूं

सोनम बाजवा ने कहा कि जब पैपराजी उनसे फोटो के लिए कहते हैं, तो समझ ही नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं जोर से हंसती हूं। मुझे नहीं पता कि पैपराजी के सामने क्या करना है। वे सैलून के बाहर भी इंतजार कर रहे होते हैं। मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं अभी-अभी सैलून से निकली हूं तो उनके सामने कैसे पोज दूं। वैसे पैपराजी बहुत कूल हैं। वे आपको इतना हंसाते हैं। मुझे लगता है कि लोग सोचेंगे, यह पैपराजी के सामने क्यों हंसती रहती है? मुझे उनसे बात करने में बहुत मजा आता है। मुझे उनसे कभी-कभार मिलना अच्छा लगता है।

मुंबई में पैपराजी कल्चर अपनी जड़ें जमा चुका है

हालांकि, एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि कभी-कभी पैपराजी प्राइवेसी वाली जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन कभी-कभी, आप अभी-अभी सोकर उठे होते हैं। आपने एक कप कॉफी भी नहीं पी होती। आपको जिम के लिए देरी हो रही होती है। जैसे ही आप जिम पहुंचते हैं, आपको पैपराजी दिख जाते हैं। आपका चेहरा सूजा हुआ होता है।

हो सकता है कि आप पिछली रात से सोए न हों। आपने पर्याप्त पानी भी नहीं पिया हो। लेकिन पैपराजी आपका इंतजार कर रहे होते हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि मुंबई में पैपराजी कल्चर कितनी गहराई से जड़ जमा चुकी है। हर कोई सतर्क हो जाता है। सोचिए अगर मैं आपको जागने के 30 मिनट के अंदर ही पकड़ लूं। आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा होता है।

लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारे काम का हिस्सा है। अब यह कल्चर स्थापित हो चुका है। मुंबई में पैपराजी का कल्चर बन चुका है। इसलिए, मैं हमेशा खुद से कहती हूं हमेशा तैयार रहो कि पैपराजी वहां होंगे। चाहे आप कहीं भी जा रहे हों।

जैकलीन ने दी थी ये खास सलाह

इस दौरान सोनम ने करीबी दोस्त जैकलीन फर्नांडीज की सलाह को याद करते हुए कहा कि एक बार जैकलीन ने मुझसे कहा था 'वो एचडी जूमिंग कैमरे खतरनाक होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि वे उस कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं।' लेकिन फिर भी इंसान भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूं। कभी-कभी मैं कहती हूं, पैपराजी वन्यजीव फोटोग्राफी के कैमरे ले जा रहे हैं।

तो, तैयार रहें। या मास्क पहनें। यह बहुत अच्छा तरीका है। जैकलीन खुद भी इसका पालन करती हैं। वह ज्यादातर मास्क में ही रहती हैं। लेकिन पैपराजी बहुत अच्छे हैं। कई बार जब मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कृपया आज मेरी तस्वीरें न लें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वे हमेशा मेरी बात सुनते हैं। वे हमेशा इसका सम्मान करते हैं। और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं।

'पिट सियापा' में नजर आएंगी सोनम

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनम बाजवा अगली बार रूपिंदर चहल द्वारा निर्देशित आगामी पंजाबी कॉमेडी-ड्रामा 'पिट सियापा' में नजर आएंगी। 1 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म में सोनम बाजवा के साथ परमवीर सिंह चीमा भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। कहानी निम्मी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार सोनम निभा रही हैं।

'मुझे घुटन महसूस नहीं होती'

जैकी भगनानी क्यों रकुल प्रीत से शादी को मानते हैं सिचुएशनशिप?

निर्माता-अभिनेता जैकी भगनानी ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के साथ अपनी शादी को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने बताया कि शादी के बाद क्या बदलाव आया और वो अपने रिश्ते को किस तरह मानते हैं

रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी बी-टाउन के क्यूट कपल में से एक हैं। दोनों अक्सर साथ में कपल गोल देते रहते हैं। हाल ही में जैकी भगनानी ने अपने रिश्ते को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि शादी के बावजूद वह अपने रिश्ते को सिचुएशनशिप की तरह मानते हैं। साथ ही जैकी ने आपस की बॉन्डिंग को लेकर भी बात की।

साथ में हम काफी खुश हैं

हाल ही में यूट्यूब चैनल जिंगाबाद के एक एपिसोड में जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह शामिल हुए। इस दौरान दोनों ने शादी के कारणों और अपने रिश्ते में आए बदलावों के बारे में बात की। जैकी ने बताया कि हमने एक-दूसरे से कहा कि अब हम 20-21 साल के नहीं हैं। हम दोनों ने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से खुशमिजाज इंसान हूं।

मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं कर रहा जो मेरे जीवन की कमी को पूरा कर सके, क्योंकि अगर मैं उदास रहूंगा, तो चाहे कोई भी मेरे जीवन में आए, मैं उदास ही रहूंगा। तुम भी व्यक्तिगत रूप से खुश हो। साथ में हम और भी खुश हैं।

इस पर रकुल ने कहा कि वे एक-दूसरे के जीवन की कमी को पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे छुट्टी पर नहीं ले गए, इसलिए मैं दुखी हूं। मैं अकेले भी छुट्टी पर जा सकती हूं। मुझे लगता है कि जीवन में बात करने के लिए और भी महत्वपूर्ण बातें हैं।

मैं कुछ भी नहीं छिपाता

इस दौरान जैकी ने कहा कि रकुल और मैं शादीशुदा हैं, लेकिन हमारा रिश्ता एक तरह का सिचुएशनशिप है। इसका मतलब है कि हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि शादी इसी वजह से हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उससे हर बात खुलकर कह सकता हूं।

अगर रकुल के आस-पास होने पर मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, तो मैं स्पीकरफोन पर बात करने में जरा भी संकोच नहीं करता। यह जताते हुए कि मैं अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं कुछ भी नहीं छिपाता, इसलिए मुझे घुटन महसूस नहीं होती।

2024 में हुई थी दोनों की शादी

रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने 21 फरवरी 2024 को शादी करने से पहले तीन साल तक डेटिंग की। उन्होंने गोवा में एक खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग की। रकुल और जैकी ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की आधिकारिक तस्वीरें साझा की थीं। शादी में रकुल ने गुलाबी-पीच रंग का लहंगा पहना था, जिस पर ढेर सारे हीरे जड़े हुए थे।

यामी गौतम ने इस फिल्म के लिए सीखी 'कुरान'

निर्देशक ने किया खुलासा, बोले- 'हमने इस्लामी कानून को समझने में...'

यामी गौतम अपनी अलग तरह की भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यामी गौतम की फिल्म के एक निर्देशक ने खुलासा किया है कि अभिनेत्री ने उनकी फिल्म के लिए कुरान सीखी थी।

फिल्म निर्माता सुपन वर्मा और यामी गौतम ने हाल ही में साथ में एक फिल्म की थी। इस फिल्म को लेकर निर्देशन ने कई खुलासे किए हैं। साथ ही यह भी बताया कि इस फिल्म के लिए यामी गौतम को कुरान सीखनी पड़ी थी।

किस फिल्म के लिए यामी ने सीखी कुरान?

फिल्म 'हक' नवंबर 2025 में रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य भूमिकाओं में यामी गौतम और इमरान हाशमी हैं। इस फिल्म के लिए यामी ने कुरान पढ़ना सीखा था। सुपन वर्मा ने हाल ही में बीबीसी को बताया कि यामी ने अपनी भूमिका के लिए कुरान का अध्ययन किया था। फिल्म बनाने के लिए टीम ने इस्लामी कानून को समझने में डेढ़ साल का समय लगाया।

सुपन ने आगे कहा कि आजकल 'गलत सूचनाओं का युग' है, इसलिए उन्होंने फिल्म में सही और तर्कसंगत जानकारी दिखाने की कोशिश की है। यामी गौतम ने भी फिल्म की अच्छी समीक्षाओं पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि लोगों की ईमानदार राय और सकारात्मकता उन्हें बहुत अच्छी लग रही है।

'हक' की कहानी

'हक' 1970 के दशक की कहानी को दिखाती है। यामी गौतम ने शाजिया बानो नाम की एक वकील की पत्नी का रोल निभाया है। उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें भरण-पोषण देने से मना कर दिया। इसके बाद शाजिया अदालत में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती हैं।

'हक' ओटीटी पर है उपलब्ध

40 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म 'हक' ने करीब 30 करोड़ रुपये ही कमाए। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह ज्यादा सफल नहीं हो पाई। सिनेमाघरों के बाद 'हक' ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है। यह फिल्म न्याय के मुद्दों पर आधारित है, जिसे अब नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।

आलिया कुरैशी कौन हैं? विजय वर्मा के साथ सैर-सपाटे पर निकलकर बटोरी चर्चा

अभिनेमा विजय वर्मा की सीरीज मटका किंग का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर हो चुका है। इस सीरीज से चर्चा बटोरने के अलावा, अभिनेता अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। दरअसल, हाल ही में विजय को एक लड़की के साथ देखा गया। बस फिर क्या सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें लेकर अटकलें लगानी शुरू कर दीं। फैंस जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर अभिनेता के साथ दिखी रहस्यमयी लड़की कौन है।

मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर विजय के साथ नजर आई रहस्यमयी लड़की असल में अभिनेत्री आलिया कुरैशी हैं। अभिनय के अलावा, आलिया को गायिकी के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने करियर की शुरुआत फरहान अख्तर द्वारा निर्मित सीरीज इटर्नली कन्फ्यूज्ड एंड ईगर फॉर लव से की थी। बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 के बाद आलिया ने शाहरुख खान की फिल्म जवान से बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इसमें उन्होंने जानवी नाम की लड़की का किरदार निभाया था।

उधर विजय और आलिया को साथ देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं? कुछ ने तो दोनों को बधाई देनी शुरू कर दी। फिलहाल, सवालों की बौछार पर विजय या आलिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें, विजय पहले तमन्ना भाटिया के साथ रिश्ते में रह चुके थे। 2025 में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था।

भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। काम की व्यस्तता और समय की कमी के कारण हम अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। हालांकि, कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाकर आप अपनी दिनचर्या में स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी स्वस्थ रह सकते हैं।

समय पर खाना खाएं

खाने का समय तय करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि आप हर दिन एक ही समय पर खाना खाएं ताकि आपका पाचन तंत्र सही रहे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना एक ही समय पर खाएं। इससे आपका शरीर समय पर भोजन के लिए तैयार रहेगा और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा यह आदत आपको भूख लगने पर तुरंत कुछ भी खाने से भी रोकेगी और आप स्वस्थ रहेंगे।

पानी पीना न भूलें

भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग पानी पीने का समय नहीं निकाल पाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे आपका शरीर तर रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। अगर आप ऑफिस या काम के दौरान व्यस्त रहते हैं तो अपने डेस्क पर एक पानी की बोतल रखें और उसे समय-समय पर भरते रहें। इससे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

थोड़ा समय निकालकर व्यायाम करें

व्यस्तता के कारण व्यायाम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। आप सुबह या शाम किसी भी समय 20-30 मिनट की सैर कर सकते हैं या हल्की-फुल्की कसरत कर सकते हैं, जैसे योग या स्ट्रेचिंग। अगर समय की कमी है, तो लंच ब्रेक में थोड़ी देर टहलें या ऑफिस के पास पार्क में जाकर कुछ मिनट टहलें। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और मानसिक तनाव भी कम होगा।

पर्याप्त नींद लें

भागदौड़ भरी जिंदगी में पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि आप हर रात कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके। अगर आप देर रात तक काम करते हैं तो सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी नींद प्रभावित होती है। इसके बजाय किताब पढ़ें या ध्यान लगाएं ताकि आपकी नींद अच्छी हो सके।

संतुलित आहार अपनाएं

संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शामिल करें ताकि आपका शरीर सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त कर सके। जंक फूड से बचें और घर का बना खाना ही खाएं ताकि आपकी सेहत बेहतर बनी रहे। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी स्वस्थ रह सकते हैं। इन आदतों को नियमित रूप से अपनाने पर आपका जीवन खुशहाल और सक्रिय रहेगा।

खास खबर

प्रदेश में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, आपूर्ति पूरी तरह सामान्यः खाद्य विभाग

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के साथ ही आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संपर्क में है, ताकि प्रदेश की ईंधन आवश्यकताओं की निर्बाध पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आपूर्ति की साप्ताहिक समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। शासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रदेश में संचालित 2516 पेट्रोल पंपों तथा तीनों प्रमुख ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध है। मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक पेट्रोल आवश्यकता 1.01 लाख किलोलीटर के विरुद्ध 1.27 लाख किलोलीटर (126 प्रतिशत) की आपूर्ति की गई। वहीं अप्रैल 2026 में 23 अप्रैल तक 1.60 लाख किलोलीटर पेट्रोल प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार मार्च में डीजल की आवश्यकता 1.64 लाख किलोलीटर के मुकाबले 3.00 लाख किलोलीटर (183 प्रतिशत) आपूर्ति हुई, जबकि अप्रैल 2026 में 23 अप्रैल तक 1.38 लाख किलोलीटर डीजल की आपूर्ति हो चुकी है।

एक्सटेंशन रिफॉर्म (आत्मा) योजना से गोविंद जायसवाल की बढ़ी आमदनी

रायपुर। कृषि विभाग की एक्सटेंशन रिफॉर्म (आत्मा) योजना किसानों के लिए आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन रही है। इसका सफल उदाहरण मुंगेली जिले के कृषक गोविंद जायसवाल हैं, जिन्होंने योजना के तहत सरसों फसल से बेहतर लाभ अर्जित किया है। रबी वर्ष 2025-26 में आत्मा योजना के अंतर्गत उन्हें सरसों की उन्नत किस्म पी.एम.-32 का बीज 01 एकड़ क्षेत्र के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही उनके गांव में कृषक खेत पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। कृषक जायसवाल ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से उन्हें बीज उपचार, खरपतवार प्रबंधन एवं सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट एफिड से बचाव के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी दी गई। साथ ही कृषि विभाग द्वारा फफूंदनाशक एवं कीटनाशक दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। उन्होंने आगे बताया कि उन्नत तकनीकों के उपयोग और विभागीय मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप प्रति एकड़ लगभग 06 क्विंटल सरसों का उत्पादन प्राप्त हुआ। सरसों के उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी के कारण उन्हें लगभग 25 हजार रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। श्री गोविंद जायसवाल ने इस सफलता के लिए कृषि विभाग एवं आत्मा योजना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने उनकी खेती को लाभकारी बनाया है।

न्यू एज मीडिया में दक्ष बनें जनसंपर्क अधिकारी : रजत बंसल

प्रचार-प्रसार कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन जिलों के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने नवा रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में जनसंपर्क संचालनालय और जिला जनसंपर्क अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि वर्तमान दौर में जनसंपर्क अधिकारियों को न्यू एज मीडिया की सभी विधाओं में दक्ष होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ तकनीक और संचार के नए माध्यमों को अपनाना ही प्रभावी जनसंपर्क की कुंजी है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनसंपर्क का कार्य अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण है, इसलिए इसे पूरी गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोताही से बचना जरूरी है। जनसंपर्क अधिकारी शासन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि परिणाम के अनुरूप हर अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा।

बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि मंत्रिगणों, विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिले के कलेक्टरों के साथ नियमित संपर्क और समन्वय बनाएं। इससे सूचनाओं का समयबद्ध और प्रभावी आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा, जो शासन की योजनाओं के सही क्रियान्वयन और प्रचार के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जनसंपर्क आयुक्त ने आगामी एक मई से शुरू हो रहे प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के प्रचार-प्रसार की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर माध्यम का प्रभावी उपयोग कर योजनाओं की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है।

उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि राज्य में हो रहे विकास कार्यों और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के वास्तविक अनुभवों को वीडियो पोस्ट और समाचारों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जाए। इससे अन्य लोगों को भी इनका लाभ लेने के लिए प्रेरणा मिलती है।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के साथ सतत संपर्क और समन्वय बनाए रखा जाए, ताकि योजनाओं की उपलब्धियों और सरकार के कार्यों का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

जनसंपर्क आयुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी सक्रिय और जिम्मेदार तरीके से कार्य करें ताकि शासन की योजनाएं आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंच सकें वहीं उन्होंने प्रचार-प्रसार कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन जिला जन संपर्क अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए है।

बैठक में अपर संचालक सर्वश्री उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी, आलोक देव और श्रीमती हर्षा पौराणिक सहित संचालनालय और जिलों के जिला जनसंपर्क अधिकारी मौजूद थे।

केलो विहार के पात्र हितग्राहियों को मिला मालिकाना हक

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सृजन कक्ष में केलो विहार शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति, रायगढ़ के पंजीकृत सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा किया गया।

इस दौरान मंत्री चौधरी ने समिति के सदस्यों से सीधे संवाद करते हुए आवासीय सुविधाओं के विस्तार, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को आवासीय अधिकार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मंत्री चौधरी ने कहा कि केलो विहार पट्टा प्रकरण लंबे समय से लंबित और संवेदनशील मुद्दा रहा है। कई लोगों ने वर्षों पहले अपने घर बनाए, लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया था। अब पट्टा मिलने से उनके सपने साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार और प्रशासन संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं, तभी जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव संभव होता है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक हितग्राहियों को उनके अधिकार दिलाना संतोष का विषय है।

कार्यक्रम में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न श्रेणियों में भूमि आवंटन के लिए मांग पत्र एवं पट्टों का वितरण किया गया। 2400 वर्गफुट श्रेणी में डॉ. धनराज प्रसाद साहू, दुलीचंद देवांगन एवं एस.एच. खोड़यार को, 1800 वर्गफुट श्रेणी में भवानी शंकर पटनायक को, 1500 वर्गफुट श्रेणी में आई.एस. परिहार, केदारनाथ प्रधान एवं बासंती सरकार को, 1200 वर्गफुट श्रेणी में खगेश्वर पटेल एवं मथुरा प्रसाद नामदेव को तथा 960 वर्गफुट श्रेणी में सूर्यकुमार पांडा, त्रिलोकी नाथ पुजारी, श्रीवत्स पांडा एवं बालकृष्ण डनसेना को पट्टा प्रदान किया गया। जिला प्रशासन के अनुसार प्रथम चरण में कुल 103 पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है और शेष प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत बबन पठारे, अपर कलेक्टर रवि राही, संयुक्त कलेक्टर राकेश गोलछा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, समिति पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सुशासन का स्वर्णिम अध्यायः दक्ष वैद्य

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सोशल मीडिया प्रदेश सहप्रभारी एवं हिन्द सेना युवा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्ष वैद्य साहू ने प्रदेश के यशस्वी, संवेदनशील एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान हेतु विशेष हेल्पलाइन प्रारंभ करने के दूरदर्शी निर्णय का स्वागत किया है। साहू ने कहा कि यह हेल्पलाइन 'अंत्योदय' से 'सर्वोदय' तक की यात्रा को साकार करने वाला सेतु है। यह केवल एक फोन नंबर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की 'जनता ही जनार्दन' की भावना का जीवंत प्रमाण है। अब सुदूर अंचल का अन्नदाता किसान हो या स्वरोजगार की राह देखता युवा, नारी सशक्तिकरण की आकांक्षी बहन हो या वृद्धावस्था पेंशन की प्रतीक्षा करता बुजुर्ग — हर व्यक्ति अपनी बात बिना किसी बाधा, बिचौलिए या विलंब के सीधे शासन के शीर्ष तक पहुंचा सकेगा।

दक्ष वैद्य साहू ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'सेवा ही संगठन, सुशासन ही संकल्प' के मंत्र को जिस दृढ़ता से धरातल पर उतारा है, यह हेल्पलाइन उसका स्वर्णिम उदाहरण है। फसल बीमा, खाद-बीज, सिंचाई, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून-व्यवस्था अथवा महिला सुरक्षा से जुड़ा कोई भी विषय अब एक कॉल पर दर्ज होगा और समयबद्ध, जवाबदेह प्रणाली से उसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल छत्तीसगढ़ को डिजिटल सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

साहू ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में जनता अपनी फरियाद लेकर कार्यालयों के चक्कर काटती थी, परंतु आज डबल इंजन की भाजपा सरकार स्वयं जनता के द्वार पर दस्तक दे रही है। यही 'जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार' का वास्तविक स्वरूप है।

दक्ष वैद्य साहू ने संकल्प व्यक्त किया कि किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर के नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता इस जनकल्याणकारी हेल्पलाइन को गाँव-गाँव, घर-घर तक पहुंचाने के लिए जन-जागरण अभियान चलाएगा, ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय और सुविधा की रोशनी पहुंचे।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने दिलाई जनगणना शपथ

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सभी को आग्रह करते हुए कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जो देश की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में आधार प्रदान करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वगणना प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

श्री अग्रवाल ने कहा कि जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत जिले में प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 16 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है, जो 30 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक किया जाएगा। इसी क्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट अंबिकापुर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को जनगणना की शपथ दिलाई।

शपथ के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने यह संकल्प लिया कि वे 1 मई तक चलने वाली जनगणना प्रक्रिया को स्वयं पूर्ण करेंगे तथा समाज के अन्य लोगों को भी इसमें भागीदारी के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही यह भी शपथ ली गई कि जनगणना प्रारंभ होने पर प्रगणकों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के सही एवं पूर्ण उत्तर प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर शपथ में यह भी संकल्प व्यक्त किया गया कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सभी जनगणना 2027 के दौरान अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे और देश के समग्र विकास, सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तिकरण में अपनी सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।

हर प्रतिभा को मिलेगा मंच, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का संवरेगा भविष्य : अरुण साव

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले के ग्राम अखरार में आयोजित रात्रिकालीन विधायक क्रिकेट कप प्रतियोगिता में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने विजेता टीम एसके हंटर औराबांधा को जीत की बधाई दी और उप विजेता अखरार इलेवन टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

उप मुख्यमंत्री साव ने इस अवसर पर खिलाड़ियों व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि फाइनल मुकाबले में युवाओं का जोश और ऊर्जा क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पांच टीमों को क्रिकेट किट वितरित किए और सभी खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सारिसताल के बागेश्वर इलेवन, अखरार इलेवन, उरई कछार इलेवन, एसपी इलेवन सरईपटेरा और प्रिंस इलेवन कंसरी को क्रिकेट किट प्रदान किए।

श्री साव ने कहा कि गांव-गांव से खेल प्रतिभाएं निकलें, यही हमारा लक्ष्य है। खेल के माध्यम से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, जो जीवन में सफलता दिलाने में मददगार साबित होता है। खेल युवाओं को स्वस्थ जीवन, अच्छे संस्कार और बेहतर समन्वय की सीख देता है।

मुंगेली जिला पंचायत की सभापति अनिता साहू और जनपद पंचायत के सभापति वेदराम पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, खेलप्रेमी और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वंचितों की आवाज अब सीधे पहुंचेगी शासन तक : रत्नावली

राशन से लेकर महिला सुरक्षा तक, हर समस्या का समाधान, सशक्त नारी समृद्ध छत्तीसगढ़ का मार्ग प्रशस्त करेगी

श्रीकंचनपथ समाचार

मुंगेली। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व सदस्य रत्नावली कौशल ने प्रदेश के संवेदनशील एवं जननायक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन' प्रारंभ करने के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह हेल्पलाइन 'सुशासन तिहार' की भावना को साकार करने वाली क्रांतिकारी पहल है।

मुख्यमंत्री जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भाजपा की सरकार केवल घोषणाओं की नहीं, बल्कि धरातल पर परिणाम देने वाली सरकार है। अब प्रदेश की माताएं-बहनें, किसान भाई, श्रमिक, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के बंधु एवं दिव्यांगजन अपनी पीड़ा को बिना किसी संकोच, बिचौलिए या कार्यालयों के चक्कर काटे सीधे शासन तक पहुंचा सकेंगे।

रत्नावली कौशल ने कहा कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह हेल्पलाइन सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का नया संबल बनेगी। घरेलू हिंसा, राशन-पेंशन में अनियमितता, स्व-सहायता समूहों की समस्या, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं या कन्या शिक्षा से जुड़ी कोई भी शिकायत अब एक कॉल पर दर्ज होगी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह 'नारी शक्ति वंदन' के संकल्प को सशक्त करने वाला कदम है।

रत्नावली कौशल ने अनुसूचित जाति वर्ग की पूर्व प्रतिनिधि होने के नाते कहा कि कांग्रेस शासन में वंचित समाज की आवाज दबा दी जाती थी, फाइलें दफ्तरों में धूल खाती थीं। परंतु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' को चरितार्थ करते हुए शासन को सीधे गरीब की झोपड़ी तक पहुंचा दिया है। छात्रवृत्ति, जाति प्रमाण पत्र, आवास योजना, सामुदायिक भवन या अत्याचार निवारण से जुड़े प्रकरणों में अब तत्काल सुनवाई होगी। रत्नावली कौशल ने कहा कि यह हेल्पलाइन 'डिजिटल छत्तीसगढ़' और 'संवेदनशील प्रशासन' का संगम है। मुख्यमंत्री जी की यह पहल बताती है कि जब नीयत साफ हो और नेतृत्व सशक्त हो, तो व्यवस्था स्वयं जनता के द्वार पर आती है।

रत्नावली कौशल ने संकल्प व्यक्त किया कि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विभा अवस्थी के नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता इस हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार गांव-गांव, वार्ड-वार्ड तक करेगी। स्व-सहायता समूहों, मितानिनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठी बहन तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।

रत्नावली कौशल ने प्रदेश की मातृशक्ति एवं समस्त नागरिकों से आह्वान किया कि मुख्यमंत्री जी की इस जनहितकारी पहल का भरपूर उपयोग करें और 'सशक्त नारी — समृद्ध छत्तीसगढ़' के निर्माण में भागीदार बनें। रत्नावली कौशल ने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके संवेदनशील नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मातृशक्ति के सम्मान, सामाजिक न्याय और सुशासन का नया कीर्तिमान स्थापित करेगा।

महतारी वंदन योजना : प्रदेशभर में महिलाओं को आर्थिक संबल, आत्मनिर्भरता की नई दिशा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए संचालित महतारी वंदन योजना आज पूरे प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस योजना के माध्यम से लाखों महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। नियमित रूप से उनके बैंक खातों में पहुंच रही सहायता राशि से वे न केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रही हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। सक्ति जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत भूरसीडीह की निवासी श्रीमती नवधा बाई पटेल इस योजना के सकारात्मक प्रभाव का जीवंत उदाहरण हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राप्त मासिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में आ रही है, जिससे घरेलू आवश्यकताओं—जैसे राशन, बच्चों की जरूरतें एवं अन्य खर्चों—की पूर्ति अब सहज हो गई है। पहले सीमित आय के कारण जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब वह काफी हद तक कम हो गया है। इस योजना ने उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता के साथ विश्वास और सम्मान की भावना को भी मजबूत किया है।

खास खबर

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह पकड़ाया

रायगढ़। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का रायगढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने एक रिटायर्ड अधिकारी को झांसा देकर करीब 37 लाख रुपये की ठगी की थी। आरोपी खुद को टेलीकॉम विभाग, फर्जी आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को डराते थे। वे पीड़ितों को फोन कर कहते थे कि उनके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज है और उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद वीडियो कॉल, फर्जी दस्तावेज और मानसिक दबाव बनाकर उनसे बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। पुलिस कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजेक्शन ट्रेल के जरिए गिरोह तक पहुंच बनाई। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई संदिग्ध बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है।

5.6 किलो गांजा के साथ हिस्ट्रीशीटर मोंटू मालेकर गिरफ्तार

राजनांदगांव। डोंगरगढ़ में नशे के कारोबार पर पुलिस ने ऐसा वार किया कि लंबे समय से सक्रिय हिस्ट्रीशीटर जाल में फंस गया, 23 अप्रैल 2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर जेल रोड चौथान मोड़ के पास पुलिस टीम ने घेराबंदी की और मोटरसाइकिल 5014 पर सवार दो संदिग्धों को रोकते ही बड़ा खुलासा हुआ, बाइक पर सवार मोहित उर्फ मोंटू मालेकर (35) निवासी जेल रोड वार्ड नंबर 21 और उसके साथ एक 16 वर्षीय विधि से संघर्षरत बालक गांजा की खेप लेकर जा रहे थे, तलाशी में 5.610 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी मोहित उर्फ मोंटू मालेकर कोई साधारण नाम नहीं बल्कि अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है जिसके खिलाफ पहले से 10 गंभीर मामले दर्ज हैं जिनमें आर्म्स एक्ट, लूट, चोरी, मारपीट और जैसे अपराध शामिल हैं, पुलिस ने मौके पर ही एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।

तेज रफ्तार बाइक खंभे से टकराई, 1 युवक की मौत

रायगढ़। गुरुवार सुबह तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। रूडूकेला निवासी लीला राम चौहान ने बताया कि उनका नाती कृष्णा चौहान अपने दोस्त खगेश्वर भगत के साथ सुबह करीब 7 बजे बिना बताए बाइक लेकर निकला था। पोतरा रोड पर मोहरलाला भगत के घर के पास लापरवाही से चलाते हुए बाइक खंभे से टकरा गई। हादसे में कृष्णा की मौके पर मौत हो गई, जबकि खगेश्वर गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रोमांस के दौरान छत से गिरा कपल, प्रेमी की मौत

रेलिंग पर हाथ-पकड़कर बैठे थे, नशे में बैलेंस बिगड़ा; लड़की के कमर की हड्डी टूटी

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रोमांस के दौरान छत से नीचे गिरने से प्रेमी की मौत हो गई। 21 अप्रैल को चिरंजीव पांडे (23) और गरिमा सिंह (23) अभिलाषा परिसर के 3 मंजिला छत पर मौजूद थे, जहां देर रात दोनों ने शराब पी और रेलिंग पर हाथ पकड़कर बैठे थे। इस दौरान बैलेंस बिगड़ने से गिर पड़े।

मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। नीचे गिरते ही दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। बॉयफ्रेंड दर्द से कराहते हुए चिल्लाने लगा। वहीं गर्लफ्रेंड भी रोने लगी। कुछ ही देर में दोनों की आवाज बंद हो गई थी। घटना की जानकारी अगले दिन सुबह लोगों को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। लड़की के कमर और रीढ़ की हड्डी टूटी है।

3 साल से था अफेयर

जांच में पता चला है कि, दोनों के बीच पिछले 3 साल से अफेयर था। चिरंजीव पांडे (23) शुभम कॉम्प्लेक्स परिसर के पास रहता था और चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी में काम करता था। इसके साथ ही जोमेटो में डिलीवरी ब्वॉय का भी काम करता था, जबकि गरिमा शादी डॉट काम में काम करती थी। घटना 21 अप्रैल की रात की है। दोनों अभिलाषा परिसर के EWS कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 34 के छत पर मौजूद थे, तभी रात 3 बजे हादसा हुआ। दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। लड़के की सिर फटने से जान चली गई। जबकि लड़की बुरी तरह से घायल होकर बेहोश पड़ी थी। देर रात होने के कारण कोई उनके चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाया। सुबह 6 बजे के आसपास लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गर्लफ्रेंड बोली- बॉयफ्रेंड को बचाने के चक्कर में गिरे

पुलिस इस घटना को पहले आत्महत्या मान रही थी, लेकिन लड़की ने होश में आने के बाद पूरी बात बताई। लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि बॉयफ्रेंड शराब के नशे में लड़खड़ा रहा था। वह छत से गिर रहा था, जिसे बचाने के चक्कर में दोनों तीन मंजिला मकान से नीचे गिर गए।

गर्लफ्रेंड की कमर और रीढ़ की हड्डी टूटी

इस हादसे में गर्लफ्रेंड गरिमा सिंह (23) की कमर और रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार अब गरिमा नहीं चल पाएगी। वहीं इस मामले में एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि ये आत्महत्या नहीं घटना है। इसकी जांच की जा रही है।

पुलिस का बड़ा एक्शन, पिकअप से 6 मवेशी बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। चिखली चौक पर रात के सन्नाटे में दौड़ रही एक संदिग्ध पिकअप ने ऐसा राज खोला जिसने पशु क्रूरता और अवैध परिवहन के काले खेल को बेनकाब कर दिया, 23 अप्रैल 2026 की देर रात जैसे ही पुलिस की नजर 1007 नंबर की पिकअप पर पड़ी, तुरंत घेराबंदी कर वाहन को रोका गया, पूछताछ और तलाशी में जो सामने आया उसने हर किसी को झकझोर दिया।

वाहन के भीतर 6 मवेशियों को ठूंस-ठूंस कर बिना चारा-पानी के अमानवीय हालत में भरकर ले जाया जा रहा था, प्रार्थी युवराज साहू की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने मौके पर ही सख्त कार्रवाई करते हुए निर्मल मनेश्वर (38) निवासी मुंडीवाड़ा, तुलसीराम नागेश्वर (60) और जयपाल नागेश्वर (43) निवासी घोपटोला मुंडीवाड़ा थाना कटंगी जिला बालाघाट तथा भगतराम खरे (43) निवासी बोरीखुर्द थाना अरी जिला सिवनी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों पर छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4 और 6 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के तहत मामला दर्ज किया गया। दुर्ग पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि पशु क्रूरता और अवैध परिवहन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

जानकारी होते हुए विवाहित पुरुष पर धोखाधड़ी-रेप का आरोप गलत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला- महिला को पता था प्रेमी शादीशुदा, यह झांसा नहीं, आरोपी बरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप और धोखाधड़ी केस में अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय एस अग्रवाल ने कहा अगर महिला को पहले से पता हो कि पुरुष शादीशुदा है और उसके साथ संबंध बनाती है, तो बाद में वह उस पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने या धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा सकती।

हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ निचली अदालत से आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही महिला की अपील को खारिज कर दी है। इस मामले में महिला ने खुद पैरवी की।

डोंगरगढ़ की रहने वाली महिला के अनुसार उसकी शादी 8 मई 2008 को महेश गंजीर के साथ हुई थी। 21 जनवरी 2009 को शादी का इकरारनामा भी तैयार किया गया था। महिला का दावा था कि इसके बाद दोनों साथ रह रहे थे। इस दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसने अलग-अलग यात्राओं पर 85 हजार रुपए खर्च किए, लेकिन जब उसने पैसे देने से मना किया तो पति महेश ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद महिला ने महेश पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए निचली अदालत में मामला पेश किया था।

कोर्ट ने पाया कि महिला के दावों में कई विरोधाभास थे। रिकॉर्ड के अनुसार महिला की ओर से पहले दिए गए नोटिस और पुलिस शिकायत में शादी की निश्चित तारीख का जिक्र नहीं था, बल्कि उसमें केवल यह कहा गया था कि आरोपी ने शादी के बहाने मई से सितंबर 2008 के बीच शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा महिला के एक अन्य नोटिस से यह स्पष्ट होता है कि वह अच्छी तरह जानती थी कि महेश पहले से शादीशुदा है। महिला को उसकी पहली पत्नी का नाम भी पता था। लिहाजा कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।

पहली पत्नी जीवित, इसलिए धोखाधड़ी नहीं

महिला ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। केस की सुनवाई के दौरान अपील करने वाली महिला ने खुद पैरवी की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि आईपीसी की धारा 493 के तहत अपराध का मुख्य तत्व धोखाधड़ी है, जिसमें पुरुष महिला को यह विश्वास दिलाता है कि वह उसकी वैध पत्नी है। जब महिला और पुरुष दोनों को पता हो कि वे कानूनी रूप से विवाहित नहीं हैं। पुरुष की जीवित पत्नी है तो धोखाधड़ी का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि महिला को महेश के विवाहित होने की जानकारी थी, इसलिए कोर्ट ने माना कि शादी का इकरारनामा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 और 11 के तहत पहले ही शून्य था।

सर्वाजनिक स्थलों से बाइक चुराकर गोठान के पास झाड़ियों में छिपाते थे, नाबालिग सहित 5 गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सार्वजनिक स्थानों से बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में एक नाबालिग समेत कुल 5 आरोपी शामिल हैं। आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों में खड़ी दोपहिया वाहनों को निशाना बनाते थे और चोरी के बाद उन्हें भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित गौठान की झाड़ियों में छिपाकर रख देते थे। आरोपियों के पास से 6 चोरी के वाहन भी बरामद किए गए हैं, जिनमें 5 स्प्लेंडर और 1 एक्टिवा शामिल है। आरोपी बाइक और स्कूटी को ही निशाना बनाते थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है और एक नाबालिग को अभिरक्षा में रखा गया है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी सुखदेव पाण्डेय निवासी मदर टेरेसा नगर कैम्प-01 भिलाई द्वारा 01.जनवरी 2026 को थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 25.दिसम्बर 2025 को नेहरू नगर अटल

प्रतिमा के पास से उसकी मोटर सायकल स्प्लेण्डर क्रमांक सीजी-07-सीएल 4739 अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर ली गई। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 24.अप्रेल.2026 को मुखबिर सूचना पर लक्ष्मी नगर सुपेला क्षेत्र से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा संगठित होकर अलग-अलग स्थानों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में हर्ष साहू, गजानंद यादव, देवेन्द्र यादव, अजय पटेल व एक नाबालिग शामिल है। इनके पास से स्प्लेण्डर मोटर सायकल क्रमांक सीजी-07-सीएल-4739, स्प्लेण्डर मोटर सायकल क्रमांक सीजी-04-पीएक्स-6739, स्प्लेण्डर मोटर सायकल क्रमांक सीजी-07-पीडी-6279, 2 बिना नंबर स्प्लेण्डर मोटर सायकल व एक्टिवा वाहन क्रमांक सीजी-07-बीए-4047 जब्त किया गया है। प्रकरण में संगठित रूप से चोरी करना पाए जाने पर धारा 112(2) बीएनएस जोड़ी गई। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव, सउनि मोतीलाल खुरसे, आरक्षक कमल साहू एवं संतोष निर्मलकर की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस आमजन से अपील करती है कि वाहन सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पार्क करें, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें तथा संदिग्ध व्यक्तियों/गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। संगठित संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

'तालिबानी सजा' से इंसानियत शर्मसार

आधा सिर मुंडाया, जूतों की माला पहनाई और गांव में घुमाया

श्रीकंचनपथ न्यूज

रामानुजनगर। छत्तीसगढ़ के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के पस्ता गांव से सामने आई यह घटना रोंगटे खड़े कर देती है जहां एक युवक मोहम्मद रहमान ताज को चोरी के शक में ऐसी सजा दी गई जिसने कानून और इंसानियत दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप है कि गांव के सरपंच पति और कुछ ग्रामीणों ने मिलकर युवक का आधा सिर मुंडवाया।

गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाई और फिर मारपीट करते हुए पूरे गांव में घुमाया, यह सब कुछ खुलेआम हुआ और किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई, हैरानी की बात यह है कि इस कथित सजा में युवक की पत्नी को भी नहीं बख्शा गया और उसे भी अपमान का सामना करना पड़ा, पीड़ित परिवार का दावा है कि उन पर लगाया गया चोरी का आरोप झूठा है और उनके साथ साजिश के तहत यह बर्बरता की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक संदिग्ध हालत में गांव पहुंचा था और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गांवों में कानून की जगह भीड़ का फैसला चलने लगा है और क्या कोई भी व्यक्ति बिना सबूत के इस तरह की सजा देने का हकदार हो सकता है, यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि समाज के उस खतरनाक चेहरे को भी उजागर करती है जहां शक के आधार पर इंसानियत को कुचल दिया जाता है। बहरहाल यह मामला एक चेतावनी है कि अगर ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भीड़तंत्र का यह खौफनाक चेहरा किसी के भी साथ दोहराया जा सकता है।

नशीली सिरप तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का खुलासा, 04 आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दवा कंपनी प्रतिनिधि की आड़ में प्रतिबंधित नशीली सिरप तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है। स्मृति नगर चौकी पुलिस व एसीसीयू की ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरिपियों ने फर्जी ड्रग लाइसेंस तैयार कर ई-कुरियर के माध्यम से प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप मंगाकर अवैध बिक्री करते थे। आरोपियों के पास से 800 नग नशीली सिरप, वाहन, मोबाईल एवं बिक्री रकम सहित लगभग 5 लाख रुपए का मशरुका जब्त किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार चौकी स्मृतिनगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम जुनवानी खम्हरिया रोड भिलाई के पास 03 व्यक्तियों द्वारा कोडिन युक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप बिक्री

हेतु परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर चौकी स्मृतिनगर एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित घेराबंदी कर सेण्ट्रो कार क्रमांक सीजी-07/8595 को रोककर जांच की गई। वाहन की तलाशी दौरान 07 कार्टून में प्रतिबंधित कोडीन युक्त CADI-FOS-T सिरप बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी योगेश शर्मा एवं उमेश कुमार यादव द्वारा फर्जी ड्रग लाइसेंस तैयार कर गुजरात स्थित कंपनी से इंडिया मार्ट ई-कुरियर माध्यम से नशीली सिरप मंगवाकर अवैध बिक्री करना स्वीकार किया गया।

विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी योगेश शर्मा द्वारा एक वास्तविक ड्रग लाइसेंस में एडिटिंग कर अपने नाम से फर्जी ड्रग लाइसेंस तैयार कराया गया तथा फर्जी लेटरपैड एवं सील बनवाकर उसके आधार पर कोडीन युक्त सिरप मंगाई जाती थी। उक्त सिरप को अधिक कीमत पर अन्य आरोपियों एवं स्थानीय युवाओं को बिक्री किया जाता था। प्रकरण में आरोपी महावीर जैन उर्फ रोहित एवं सतीश मेश्राम को भी गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों द्वारा प्रतिबंधित सिरप की बिक्री से अवैध धन लाभ अर्जित किया जाना तथा युवाओं को नशे का आदी बनाना पाया गया। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 8(ख), 27(क), 29 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है।

उक्त कार्यवाही में चौकी स्मृतिनगर एवं एसीसीयू टीम के अधिकारी-कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई सराहनीय रही। टीम द्वारा सूचना संकलन, घेराबंदी, आरोपियों की पतासाजी एवं त्वरित गिरफ्तारी में प्रभावी भूमिका निभाई गई। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित मादक पदार्थों, नशीली दवाओं अथवा अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। युवाओं को नशे से दूर रखने एवं समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

हॉलीडे पैकेज के नाम पर 2.94 लाख की ठगी

रायपुर। राजधानी रायपुर में हॉलीडे पैकेज के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के संचालक ने एडवांस के रूप में करीब 2.94 लाख रुपए लेकर कंपनी बंद कर दी और फरार हो गया। शिकायत के बाद तेलीबांधा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान नागेश कुमार के रूप में हुई है।

तेलीबांधा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सरस्वती नगर निवासी पीड़ित महेश सिंह राजपूत ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी नागेश, मैग्नेटो मॉल स्थित 'प्लू वेरियंट' नाम की ट्रैवल एजेंसी का संचालन करता था। उसने आकर्षक हॉलीडे पैकेज का झांसा देकर पीड़ित से एडवांस में पैसे ले लिए।

पैसे लेने के बाद नहीं मिली कोई सेवा

पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने देश-विदेश के टूर पैकेज का लालच दिया और यह भरोसा दिलाया कि पूरी व्यवस्था उसकी कंपनी करेगी। पीड़ित के अनुसार पैसे लेने के बाद न तो कोई ट्रिप बुक की गई और न ही किसी तरह की सेवा दी गई। कुछ दिनों बाद आरोपी ने अपना ऑफिस बंद कर दिया और संपर्क से बाहर हो गया।

पीड़ित के अनुसार आरोपी ने केवल उससे नहीं बल्कि अन्य लोगों से भी इसी तरह रकम लेकर ठगी की है। तेलीबांधा थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

पुलिस बोली- आरोपी को जल्द अरेस्ट किया जाएगा

इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत परआरोपी नागेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ जांच की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रेत के अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुमरदा तहसील अंतर्गत ग्राम मोतीपुर नदी घाट में राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत उत्खनन के लिए बनाए गए रैम्प को तोड़ दिया। साथ ही घाट तक पहुंचने वाले मार्ग को काटकर पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया, ताकि भविष्य में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

इससे पहले टीम द्वारा मोतीपुर नदी घाट से अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे दो माजदा वाहनों को रेत सहित जप्त किया गया। दोनों वाहनों को थाना डोंगरगांव के सुपुर्द कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

प्रमुख खबरें

बैगा पारा में जागरूकता अभियान, खुले में शौच के दुष्परिणाम बताए

एमसीबी। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पराडोल अंतर्गत बैगा पारा में ग्रामीणों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान ग्रामीणों को स्वच्छ जीवनशैली अपनाने एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। हितग्राहियों को शौचालय निर्माण के महत्व से अवगत कराया गया तथा खुले में शौच से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। बताया गया कि शौचालय न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पूरे समुदाय को संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभियान के दौरान गर्मी के मौसम में फैलने वाली बीमारियों जैसे डायरिया, लू, उल्टी-दस्त आदि से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने साफ एवं उबला हुआ पानी पीने, भोजन को ढक कर रखने, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने तथा आसपास स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी।

रेत खदानों की नीलामी ऑनलाइन, 27 अप्रैल को जिले में ई-ऑक्शन

एमसीबी। जिले में रेत खदानों के संचालन को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दिशा में प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज (साधारण रेत) उत्खनन एवं व्यवसाय नियम, 2025 के अंतर्गत रेत खदानों की नीलामी अब ई-ऑक्शन (इलेक्ट्रॉनिक नीलामी) के माध्यम से की जाएगी। जारी अधिसूचना के अनुसार मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की रेत खदानों के आवंटन हेतु इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन के अनुसार ई-ऑक्शन प्रक्रिया 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 10:00 बजे कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें पात्र आवेदक ऑनलाइन माध्यम से भाग लेकर रेत खदानों के संचालन हेतु बोली लगा सकेंगे। इस नई व्यवस्था के लागू होने से जिले में रेत खनन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही इससे शासन के राजस्व में वृद्धि होने के साथ खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा। प्रशासन ने इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

15 सालों से सघन वनक्षेत्र में चल रही अवैध कटाई

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक लाख पेड़ों की अवैध कटाई, इसरो के सैटेलाइट ने खोली पोल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन विभाग ने उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर वन्यप्राणी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण का खुलासा किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से जुटाए गए डिजिटल साक्ष्यों से यह सामने आया है कि पिछले 15 वर्षों में लगभग 106 हेक्टेयर (265 एकड़) क्षेत्र में अवैध कब्जा कर करीब एक लाख पेड़ों की कटाई की गई है।

टाइगर रिजर्व के बाहर स्थित जैतपुरी गांव के 166 लोगों द्वारा किया गया, जिनके विरुद्ध विभिन्न प्रकरण दर्ज कर उन्हें बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में यही अतिक्रमण 45 हेक्टेयर में था, जो समय के साथ बढ़कर 106 हेक्टेयर हो गया। ड्रोन सर्वे से तैयार हाई-रिजोल्यूशन इमेजरी में अतिक्रमण क्षेत्र के प्रत्येक खेत, कटे हुए पेड़ और ठूंठ को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। वहीं इसरो की कार्टोसैट सैटेलाइट इमेजरी (2006, 2008, 2010, 2012 और 2022) से वन क्षेत्र में तेजी से आई कमी का प्रमाण मिला है। जहां पहले एक हेक्टेयर में लगभग 1000 पेड़ थे, वहां अब यह संख्या घटकर मात्र 25 से 50 रह गई है।

वन विभाग के अनुसार, अतिक्रमणकारियों ने न केवल पेड़ों की कटाई की, बल्कि 'गर्डलिंग' जैसी तकनीकों का उपयोग कर वृक्षों को सुखाकर जमीन खाली की। जांच में यह भी पाया गया कि कई आरोपियों के पास राजस्व भूमि पहले से मौजूद होने के बावजूद लालचवश वन भूमि पर कब्जा किया गया।

यह क्षेत्र उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व का कोर जोन है और महानदी का उद्गम स्थल भी है। यहां हाथी, तेंदुआ और बाघ जैसे वन्यप्राणियों का महत्वपूर्ण आवास है। अतिक्रमण से क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 7 वर्ष तक और लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत 3 वर्ष तक सश्रम कारावास का प्रावधान है। साथ ही अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को भी अटैच किया जाएगा।

आधी रात को नींद खुली तो टूटी पड़ी थी दीवार, सामने खड़ा था मतवाला हाथी

श्रीकंचनपथ समाचार

सरगुजा। सरगुजा संभाग के एक गांव में बीती रात खामोशी उस वक्त चीखों में बदल गई जब अचानक जोरदार धमाका हुआ। घरवालों ने बाहर झांका तो सामने खड़ा था एक मतवाला हाथी। मामला ग्राम मेंढारी के सेमरिया पार का है।

राजेश कुशवाहा के घर पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने घर की सामने की दीवार को तोड़ डाला जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इस हाथी ने पहले भी हमला किया था और घर में रखा गेहूं खा गया था। लगातार हो रहे नुकसान के बावजूद पीड़ित परिवार को अब तक किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले एक महीने से यह हाथी अपने झुंड से अलग होकर इलाके में घूम रहा है और आए दिन गांव में घुसकर दहशत फैला रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सहमे हुए हैं, घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है लेकिन सवाल यही है कि क्या केवल सूचना से समाधान निकलेगा या फिर किसी बड़ी अनहोनी के बाद ही व्यवस्था जागेगी। फिलहाल यह घटना साफ चेतावनी है कि मानव और वन्यजीव के इस टकराव को समय रहते नहीं रोका गया तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं और इसकी कीमत निर्दोष ग्रामीणों को चुकानी पड़ सकती है।

छत्तीसगढ़ कोसा उद्योग : राज्यपाल ने दिया असम के सफल मॉडलों का अध्ययन करने का सुझाव

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा साड़ी, शाल और गमछा का अवलोकन किया तथा राज्य के हाथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए नवाचार, डिज़ाइन विकास और मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया।

राज्यपाल ने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कोसा साड़ी एवं शाल में डॉबी और जैकार्ड तकनीक का उपयोग कर आधुनिक डिजाइन विकसित किए जाएं। साथ ही विभिन्न आयु वर्ग की पसंद को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को आकर्षक एवं किफायती बनाया जाए, ताकि इनकी बाजार में मांग बढ़ सके।

उन्होंने उत्तर-पूर्व के प्रसिद्ध रेशम क्षेत्र असम के सुवालकुची, विजयनगर और डेमाजी क्षेत्रों के सफल मॉडल का अध्ययन कर वहां के लोकप्रिय डिज़ाइनों को छत्तीसगढ़ के कोसा वस्त्रों में समाहित करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि इससे राज्य के बुनकरों को नई पहचान मिलेगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। राज्यपाल ने कोसा साड़ी को अधिक किफायती बनाने के लिए साड़ी की बॉडी और बॉर्डर को पृथक रूप से तैयार कर नई शैली की साड़ियों के निर्माण का सुझाव भी दिया। उन्होंने विशेष रंगों एवं धागों-एक्रेलिक, स्पन और टू-प्लाई यार्न का उपयोग कर आकर्षक मोटिफऔर डिज़ाइन विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने आगामी एक माह में इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामोद्योग विभाग को राज्य की किसी एक बुनकर सहकारी समिति को गोद लेकर उसके समग्र विकास हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में ग्रामोद्योग विभाग के सचिव श्याम धावड़े, राज्य हाथकरघा संघ के सचिव एमएम जोशी, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार बुनकर सेवा केंद्र रायगढ़ के उपनिदेशक विजय सावनेरकर सहित तकनीकी विशेषज्ञों तथा डिजाइनर उपस्थित रहे।

'सरगुजा छेरी बैंक' : किराए पर बकरी ले जाओ मेमने लौटाकर आराम से हिसाब चुकता करो

श्रीकंचनपथ समाचार

सरगुजा। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में नवाचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सरगुजा जिले में 'सरगुजा छेरी बैंक' मॉडल शुरू किया गया है। बिहान के तहत जिला पंचायत द्वारा संचालित इस योजना में महिलाओं को नकद के बजाय बकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिन्हें वे किस्त के रूप में पैसे नहीं, बल्कि बकरियों के बच्चों के रूप में वापस करेंगी।

इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमगसी की सरस्वती स्व-सहायता समूह की सदस्य सोहर मणी ने 3,000 रुपये की प्रारंभिक राशि जमा कर चार बकरियां प्राप्त की हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया है।

योजना के तहत लाभार्थियों को बकरियों के साथ ही उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए 40 माह तक टीकाकरण, डिवार्मिंग और प्रजनन (एआई) जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं। लाभार्थी महिलाओं को चार वर्षों में कुल 16 मेमने 'छेरी बैंक' को लौटाने होंगे।

प्रारंभिक चरण में 50 महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। 76 बकरियों के साथ इस चक्र की शुरुआत की गई है। अनुमान है कि 4 बकरियों से 8 वर्षों में लगभग 60 से 65 मेमनों का उत्पादन हो सकता है। निर्धारित 16 मेमनों को लौटाने के बाद भी महिलाओं के पास पर्याप्त संख्या में बकरियां शेष रहेंगी, जिससे उनकी स्थायी आय सुनिश्चित होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रीष्मकालीन एहतियात

भीषण गर्मी से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता अब सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलेगी आंगनबाड़ियां

■ मुख्यमंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री ने जारी किए दिशा निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए त्वरित एवं संवेदनशील निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री साय के निर्देशानुसार 30 जून 2026 तक प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इस अवधि में बच्चों की उपस्थिति केवल सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक निर्धारित की गई है, ताकि उन्हें अत्यधिक तापमान एवं लू के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा गतिविधियाँ निर्धारित समय-सारिणी एवं कलेण्डर के अनुसार संचालित होंगी तथा पूरक पोषण आहार का वितरण नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे बच्चों के पोषण एवं शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए।

निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्र प्रातः 7:00 बजे से प्रारंभ होंगे, जिसमें बच्चों की उपस्थिति 7:00 से 9:00 बजे तक रहेगी, जबकि अन्य सेवाओं के लिए केंद्र 11:00 बजे तक संचालित रहेगा। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपने जॉब चार्ट के अनुसार शेष कार्यों का निष्पादन करेंगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि गृहभेंट के माध्यम से पोषण परामर्श सेवा को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र बंद होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घर-घर जाकर माताओं को जागरूक करेंगी।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि गर्म हवाओं, अधिक तापमान एवं लू की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन व्यवस्थाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित करें तथा जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें, ताकि जमीनी स्तर पर निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल समाप्ति उपरांत 01 जुलाई 2026 से आंगनबाड़ी केंद्र पुनः अपने सामान्य समय प्रातः 9:30 बजे से 3:30 बजे तक (6 घंटे) संचालित किए जाएंगे।

विश्व मलेरिया दिवस पर छत्तीसगढ़ का संकल्प

मलेरिया की जांच, उपचार और जनभागीदारी से बदलती तस्वीर, अब इसके पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मलेरिया संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के एक डंक से शुरू होती है। अगर समय पर पहचान न हो, तो स्थिति जटिल हो सकती है। इसलिए समय पर जांच और उपचार को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी मानी जाती है।

25 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व मलेरिया दिवस हमें न सिर्फ इस बीमारी के खतरों की याद दिलाता है, बल्कि यह भी बताता है कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों और दूरस्थ बसाहटों के कारण लंबे समय तक मलेरिया एक बड़ी चुनौती बना रहा।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 में दर्ज कुल 144886 मामलों की तुलना में वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 28836 रह गई।

मलेरिया बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए अधिक जोखिमपूर्ण होता है।

मलेरिया उन्मूलन हेतु संदिग्ध व्यक्ति की तत्काल जांच, पॉजिटिव पाए जाने पर निःशुल्क उपचार और मरीजों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही 'मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर' जैसे अभियान भी संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य अमला घर-घर जाकर जांच और दवा दे रहा है।

सुदूर वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट, मितानिन और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये टीमें न केवल जांच और उपचार कर रही हैं, बल्कि लोगों को मलेरिया से बचाव के उपायों के प्रति भी जागरूक बना रही हैं।

मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग, आसपास साफ-सफाई बनाए रखना, पानी का ठहराव न होने देना और बुखार आने पर तुरंत जांच कराना, ये सरल उपाय इस बीमारी के प्रसार को रोकने में प्रभावी हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त प्रदेश बनाया जाए। इसके लिए शासन, प्रशासन और आमजन के बीच समन्वय को और मजबूत किया जा रहा है। विश्व मलेरिया दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और मलेरिया के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ, सुरक्षित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहयोग करें।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सरकार ने दोहराई प्रतिबद्धता

मजबूत पंचायती राज से सुदृढ़ होगा भारत : मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। डबल इंजन की हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में गांवों के समग्र विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

श्री साय ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से ही गांवों का विकास होगा और अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंचायत प्रतिनिधि के रूप में की थी तथा पंच और सरपंच के दायित्व का निर्वहन किया। श्री साय ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में गांव के विकास को लेकर जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वही आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। आज हजारों जनप्रतिनिधि पंचायत से अपना सफर शुरू कर देश के उच्च सदनों तक पहुंचे हैं। गांवों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और जमीनी स्तर पर बेहतर कार्य करने से ही प्रभावी नीतियां बनती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब ग्रामीणों को पक्के मकान मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। अटल डिजिटल सेवा केंद्रों से बैंकिंग, बिजली बिल भुगतान, पेंशन और बीमा जैसी सेवाएं अब ग्रामीणों के लिए सहज हो गई हैं। महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से कई पूर्ण हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंचायतों में संचालित सभी गतिविधियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सभी विकास कार्य पूर्ण हो सकें। जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सफल की जिम्मेदारी पंचायतों की है।

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से सुशासन तिहार के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें सरचार्ज पूरी तरह माफ किया गया है और अतिरिक्त रियायत का भी प्रावधान है। श्री साय ने प्रतिनिधियों से इसका लाभ अधिक से अधिक ग्रामीणों को दिलाने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगी और सभी प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करें।

बस्तर में पंचायत राज : ए-आई टूल, सभासार और निर्णय ऐप से डिजिटल हो गई ग्राम सभाएं

श्रीकंचनपथ समाचार

जगदलपुर। बस्तर जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास और सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखी गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में जिला स्तर और विकासखंड पर आयोजित इन कार्यक्रमों में पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई।

इस विशेष अवसर पर पंचायती राज व्यवस्था की महत्ता और ग्राम स्वराज की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रणाली लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हुए जमीनी स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करती है।

ग्राम सभाओं के दौरान आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत के निर्माण हेतु संकल्प पारित किए गए और गाँव की उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने खेल, कला या अन्य विधाओं में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। इसी कड़ी में आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करने वाली 'लखपति दीदीयों का भी सम्मान किया गया। सभा में सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे गंभीर विषयों पर विशेष जोर देते हुए ग्राम विकास के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही आगामी जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रामीणों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बस्तर ने तकनीकी नवाचार के मामले में एक विशिष्ट उदाहरण पेश किया, जहाँ जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में 'निर्णय ऐप के माध्यम से सभा की फोटो और वीडियो अपलोड किए गए। साथ ही सभासार ऐप (एआई टूल) का उपयोग कर ग्राम सभा की कार्यवाही का ऑनलाइन विवरण तैयार करने की आधुनिक प्रक्रिया अपनाई गई। इस दौरान ग्राम सभा अध्यक्ष के चुनाव हेतु चक्रानुक्रम प्रक्रिया पर भी प्रस्ताव पारित किया गया।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950